शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

एक दिन पहले व्याख्याता मिले थे पीएस से, मंगलवार को दिन भर हुई भागदौड़

व्याख्याताओं की वेतन विसंगति दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग में प्रक्रिया शुरू

भोपाल (आरएनएन)। प्रदेश में उम्रदराज होकर लगातार रिटायर हो रहे व्याख्याताओं की ताकत का एहसास शिक्षा विभाग को हुआ है। एक दिन पहले ही लेक्चररों और प्राचार्य का एक दल विभाग की प्रमुख सचिव से मिला था, जहां वेतन विसंगति से होने वाले अनेक नुकसान गिनाए गए थे। अगले ही दिन मंगलवार से इस विषय में काम शुरू हो गया है। मंगलवार को मंत्रालय और लोक शिक्षण संचालनालय के बीच लगातार जानकारी जुटाने का काम चला। दूरभाष पर संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों से भी संपर्क हुए।

बताना होगा कि व्याख्याताओं ने अपनी वेतन विसंगतियों को लेकर सोमवार को स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी से मुलाकात की थी। व्याख्याता एवं प्राचार्य संवर्ग की समस्यायों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश शिक्षक संघ, प्रांतीय शासकीय शालेय व्याख्याता एवं प्राचार्य संघ, समग्र शिक्षक व्याख्याता एवं प्राचार्य कल्याण संघ, एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रमुख पदाधिकारियों क्रमशः छत्रवीर सिंह राठौर, महामंत्री शिक्षक संघ, के के गौर संभागीय अध्यक्ष शिक्षक संघ, प्रदेश अध्यक्ष अरुण विश्वकर्मा, मुकेश शर्मा एवं प्रांतीय संयोजक पीएस परिहार सहित प्रमुख प्रांतीय पदाधिकारी भरत व्यास, सुधाकर पाराशर, डॉ अनिल कुशवाहा, हरेंद्र सिंह, रविकान्त जैन, सीएस सोलंकी, बहन श्रीमती भावना शर्मा एवं श्रीमती संगीता सक्सेना सहित अन्य साथी उपस्थित रहें।

शिक्षकों को पदोन्नति पदनाम के विषय में भी सोचना होगा

इधर शिक्षक और सहायक शिक्षकों ने भी पदोन्नति पदनाम के लिए विभाग पर दबाव बनाया है। सहायक शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संयोजक सुभाष शर्मा का कहना है कि विभाग को इस विषय में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री की घोषणा को हुए पूरे 5 साल बीत चुके हैं लेकिन आज तक इसका पालन नहीं किया गया है। शर्मा का कहना है कि जबसे घोषणा हुई तब से अभी तक प्रदेश में दर्जनों शिक्षक बिना पदोन्नति पदनाम का लाभ लिए रिटायर हो गए हैं। विभाग का यह रवैया शिक्षकों के प्रति न्याय संगत नहीं कहा जाएगा।

प्रमुख सचिव शमी ने प्रमुख मुद्दों पर जताई थी सहमति

बैठक में व्याख्याता, प्राचार्य संवर्ग की समस्याओं एवं वेतन विसंगति से संबंधित सभी बिंदुओं पर प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, उप सचिव अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत संचालक लोक शिक्षण केके द्विवेदी, सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा कर की गई। दल का नेतृत्व भरत व्यास द्वारा किया गया एवं विसंगति के बारे में प्रमुख सचिव एवं सभी अधिकारियो को विस्तार से बताया। प्रमुख सचिव द्वारा ध्यान से पूरी बात सुनी एवं निर्देश दिए कि व्याख्याताओं की विसंगति संबंधी फाइल को तैयार कर मेरे अवकाश से लौटने पर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। हाईस्कूल प्राचार्य का पद समाप्त करने के संबंध में भी चर्चा की गई जिस पर प्रमुख सचिव द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

कर्मचारियों की एसीआर होगी डिजिटल इंक्रीमेंट की मिलेगी सौगात

नए साल में पंद्रह जनवरी को कर्मचारियों की रुकी पदोन्नति के निराकरण पर आएगी रिपोर्ट

शहर प्रतिनिधि, भोपाल। कर्मचारियों की नए साल में वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) डिजिटल हो जाएगी। ऐसा होने से कोई भी कर्मचारी आसानी से अपनी एसीआर देख पाएंगे। डेढ़ साल से रुके इंक्रीमेंट की सौगात भी नए साल में मिलने के आसार हैं।

नए साल में प्रदेश के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति तीन तरह से सुदृढ़ होती है। पहला इंक्रीमेंट, दूसरा मंहगाई भत्ता व तीसरा पदोन्नति। कोरोना के कारण साल 2020 में इंक्रीमेंट व मंहगाई भत्ता का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिला है, जबकि पदोन्नति का मामला सुप्रीमकोर्ट में लंबित है। नए साल में कर्मचारियों को तीनों सौगात देने की तैयारी की जा रही है। पदोन्नति को लेकर सरकार ने प्रशासन अकादमी के महानिदेशक एपी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समिति गठित की है। समिति प्रदेश में पदोन्नति पर रोक के कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार देने की नीति तैयार कर रही है। कमेटी को नए साल में पंद्रह जनवरी तक रिपोर्ट देना है।

न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए बन रही घाटे का सौदा

रिटायरमेंट पर किसी की 700 तो किसी की 1100 रुपए बन रही पेंशन

यह अंतर है पुरानी और नई पेंशन में : पुरानी पेंशन के पात्रताधारी कर्मचारियों को जिस माह वे रिटायर हो रहे हैं उस समय उनका जो मासिक वेतन है उसकी आधी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। यानी मूल वेतन 37873 रुपए है तो पेंशन बन रही है 19 हजार रुपए। इस पर महंगाई राहत अलग से यानी 20 हजार रुपए के करीब मिलते हैं।

भास्कर न्यूज . भोपाल | न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर घाटे का सौदा बन रही है। 23 साल की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त होने पर हाथ आ रहे है खाली लिफाफे और कुछ के हाथों में महज 700 से 1100 रुपए की पेंशन। दरअसल, राज्य सरकार ने प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू की है। इसमें 10 फीसदी कर्मचारी के वेतन में से कटौती और 10 फीसदी हिस्सा सरकार मिला रही है। कुल मिलाकर रिटायरमेंट पर जो कुल जमा हो रहा है उसमें से 60 फीसदी नकद दे दिया जा रहा है और बाकी 40 फीसदी राशि पेंशन फंड के नाम पर जमा कर ली जा रही है, जिसके एवज में नाम मात्र की राशि पेंशन के रूप में दी जाती है।

केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को जब न्यू पेंशन स्कीम शुरू की उसके प्रारूप में साफ था कि यह राज्यों के ऊपर निर्भर करेगा कि वे पुरानी पेंशन जारी रखना चाहते हैं या नई लागू करते हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने 2005 में पुरानी पेंशन बंद कर दी। इसमें यह उल्लेखनीय है कि 1997 से 2004 के बीच सेवा में आए कर्मचारी पेंशन के पात्र हैं, पर उनकी भी पेंशन बंद कर दी गई है। मप्र पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के महासचिव बाल गोविंद द्विवेदी का कहना है कि एनपीएस योजना में रिटायर हो रहे कर्मचारियों की पेंशन न ग्रेच्युटी खाली हाथ घर वापसी हो रही है।

शिक्षकों ने दिनभर लगाई ताकत विभाग परीक्षा कराने पर अडिग

मप्र शिक्षक संघ ने संचालनालय फिर मंत्रालय में रखा पक्ष

प्रदेश में सात हजार शिक्षकों की हो रही परीक्षा कई के जोड़ दिए गए गलत नाम

भोपाल(आरएनएन)। मौजूदा सप्ताह में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उन शिक्षकों की परीक्षा आयोजित की जा रही है जिन्होंने अपने विद्यालयों में पिछले वर्ष की 10वीं 12वीं की परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम रिजल्ट दिया है। अब इन टीचरों की परीक्षा निरस्त करने के लिए शिक्षकों के संगठन शुक्रवार की दोपहर लोक शिक्षण संचालनालय से लेकर मंत्रालय तक चक्कर काटते रहे। इन्हीं विभाग ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि परीक्षा हर हाल में होगी।

3 जनवरी को स्कूल शिक्षा विभाग 40 प्रतिशत से कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इस परीक्षा को लेकर उन शिक्षकों में दहशत है जिन का इम्तिहान कराया जाना है। शिक्षकों के संगठन भी इस परीक्षा को न्याय उचित नहीं ठहरा रहे हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक संगठन द्वारा इस संदर्भ में पहले 31 दिसंबर को अधिकारियों से मुलाकात करने की कोशिश की गई थी लेकिन नूतन वर्ष की अंतिम बेला होने के कारण अफसर कार्यालय में नहीं मिल पाए। अगले दिन शुक्रवार की दोपहर संगठन पदाधिकारियों ने मुलाकात की लेकिन आश्वासन के बाद यह साफ संकेत दे दिए गए की परीक्षा हर हाल में होगी। इधर आरोप लगाया गया है कि कई शिक्षकों के नाम गलत दिए गए। इन्होंने बेहतर परीक्षा देकर रिजल्ट दिया है उसके बावजूद परीक्षा सूची में इनका नाम रख दिया गया है।

परीक्षा हर हाल में कराई जाएगी: प्रमुख सचिव

स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने स्पष्ट कर दिया है कि 40 प्रतिशत से कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों की परीक्षा हर हाल में होगी। शाम के वक्त शासकीय अध्यापक संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने परीक्षा निरस्त करने के संबंध में प्रमुख सचिव से भेंट की थी। इस दौरान पीएस रश्मि अरुण शमी ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि शिक्षकों की परीक्षा हर हाल में होगी। इस दौरान उन्होंने संगठन के प्रतिनिधि मंडल से सवाल भी किया कि आखिर शिक्षकों को परीक्षा देने में क्या दिक्कत है। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष आरिफ अंजुम एवं उपेंद्र कौशल्य ने मांग रखी कि शिक्षक परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन उन्हें अनुत्तीर्ण होने पर सेवा से बर्खास्त ना किया जाए। इधर दोपहर वक्त मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ओपी कटिहार ने लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचकर परीक्षा निरस्त करने के लिए आयुक्त जयश्री कियावत को ज्ञापन सौंपा।

जिन्होंने अच्छा काम किया उनकी भी परीक्षा ठीक नहीं : राठौर

अधिकारियों से बात ना बनने के बाद मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री क्षत्रवीर सिंह राठौर ने कहा कि यह परीक्षा शिक्षकों को परेशान करने का एक रास्ता है। राठौर के अनुसार दक्षता आंकलन के लिए जो आंकड़े लिए गए है, उनमें ऐसे विद्यार्थियों को शामिल कर लिया गया है जो कम उपस्थिति के कारण स्वाध्याय कर दिए गए हैं। इन छात्रों का नामांकन भी है परंतु परीक्षा मे सम्मिलित नहीं हुए है। नामांकन के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले नियमित विद्यार्थियों की संख्या को आधार ना मानने से लगभग 80 फीसदी विद्यालयों के शिक्षकों को परीक्षा देनी पड़ रही है, जो न्याय उचित नहीं है।

दक्षता आंकलन के लिए विषयवार परिणाम को नहीं बनाया आधार

मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय सचिव राजीव शर्मा का कहना है कि दक्षता परीक्षा के लिए विषयवार परीक्षा परिणाम को आधार नहीं बनाया गया जो सर्वथा अनुचित है। कक्षा 10वीं परीक्षाफल 40 प्रतिशत से कम है किंतु इस परीक्षा मे शामिल आठवी के शिक्षकों जिनका परीक्षा परिणाम 40 से 100 प्रतिशत तक रहा है। उनको भी दक्षता अंतरण परीक्षा में शामिल करना एक प्रकार से संकट पैदा करना है। कक्षा नवी मे बेस्ट ऑफ फाइव के अंतर्गत छोड़े गए एक विषय मे कक्षा दसवी उसी विषय पर अनुच्छेद होने पर कक्षा दसवी के विषय शिक्षक को दोषी मान लिया गया है।

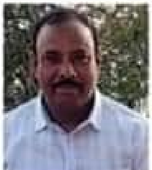

लगातार शिक्षकों से करवाया जा रहा गैर शैक्षणिक कार्य

शिक्षक नेता गौतम मणि का कहना है कि शासकीय विद्यालयों मे कक्षा नवी मे अशासकीय शालाओं के छात्र प्रवेश लेते है। इन छात्रों के कारण दसवी का परीक्षा परिणाम 40 प्रतिशत से कम होने पर अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को दक्षता परीक्षा मे शामिल किया जाना ठीक नही है। आरोप लगाया गया है कि पूरे सत्र मे शिक्षकों से बीएलओ ड्यूटी करवाई गई है। ओपन परीक्षा मदरसा बोर्ड संस्कृत बोर्ड की परीक्षा भी शिक्षकों से संपादित करवाई गई है। इन परीक्षाओं के बाद मूल्यांकन करवाना संकलन केंद्र से प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण कराना जैसे अनेक कार्यों मे शिक्षकों को संलग्न किया गया है। अब शिक्षक जब अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों मे उलझा रहेगा तो वह कैसे अपने मुख्य काम पर फोकस करेगा। विभाग को इस दिशा मे भी सोचने की जरूरत है।

शिक्षकों ने दक्षता परीक्षा के खिलाफ वाहन रैली निकाली, विधायक को दिया ज्ञापन

हाई सेकंडरी व हाई स्कूल के परीक्षा परिणामों में अनदेखी का आरोप

पीपुल्स संवाददाता ● सीहोर

editor@peoplessamachar.co.in

40 प्रतिशत या कम हाई स्कूल परीक्षा परिणाम 2019-20 के आधार पर हायर सेकंडरी, हाई स्कूल एवं कैचमेंट क्षेत्र के मिडिल स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा संबंधी आदेश को निरस्त कराने शिक्षकों ने भोपाल नाके से वाहन रैली निकालकर विधायक सुदेश राय को ज्ञापन दिया। दक्षता परीक्षा को लेकर शिक्षकों में आक्रोश है।इसके पूर्व भी स्व. यज्ञ सेन श्यामले तथा 15 शिक्षकों को दक्षता परीक्षा के आधार पर सेवानिवृत्त कर दिया था। जबकि हायर सेकंडरी और हाईस्कूल में रिजल्ट कई कारणों पर निर्भर है।

वर्षों से खाली है शिक्षकों के पद: हाई स्कूल व हाई सेकंडरी स्कूल में कई विषय के शिक्षकों के पद रिक्त हैं। वर्षों से यह पद नहीं भरे गए हैं। इसके अतिरिक्त हाई स्कूल व हाई सेकंडरी परीक्षा के आधार पर माध्यमिक शिक्षकों की भी परीक्षा ली जा रही है, जबकि वह बच्चे 2 वर्ष पूर्व ही स्कूलों से उत्तीर्ण होकर निकल चुके हैं।

शिक्षकों की सूची में भी विसंगति

अंतिम माध्यमिक सूची निकालने के पहले दावा - आपत्ति नहीं ली गई। नही समय दिया गया और परीक्षा में शामिल होने का फरमान जारी कर दिया गया। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षकों की सूची में भी कईविसंगतियां हैं।

सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 25 हजार नए शिक्षक, दस हजार स्कूल बनेंगे हाइटेक

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। स्कूल शिक्षा विभाग को नए साल में करीब 25 हजार से ज्यादा नए शिक्षक मिल जाएंगे। प्रदेश के 10 हजार स्कूल केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर नया स्वरुप लेंगे। विभागद्वारा चल रही भर्ती प्रक्रिया में करीब 25 हजार पदों पर शिक्षक इस साल पढ़ाने लगेंगे। साथ ही स्कूल शिक्षा में एक लाख शिक्षकों की कमी को पूरा करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

प्रदेश के दस हजार स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर बनाया जा रहा है। सीएम राइज के तहत यह स्कूल आगामी शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएंगे, जो हाइटेक होंगे। इस साल में विभाग ने शिक्षकों की समस्याएं सुलझाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू की है। स्कूल शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दसवीं-बारहवीं के 19 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है। इस साल बोर्ड परीक्षा का पैटर्न भी पूरी तरह बदला रहेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संस्कृत बोर्ड शिवाजी नगर में 40 करोड़ की लागत से बन रही बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। संस्कृत बोर्ड द्वारा राजधानी में बालक आवासीय विद्यालय खोला जा रहा है। यह विद्यालय इस साल स्वरूप ले लेगा। इस साल प्रदेश में बीस संस्कृत स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। साथ ही इस साल प्रदेश के 53 सरकारी स्कूलों में एलकेजी व यूकेजी की कक्षाएं शुरू होंगी। इसके साथ ही संस्कृत बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष समेत अन्य पाठ्यक्रमों के डिप्लोमा कोर्स भी इस साल से शुरू किए जाएंगे।

सरकारी कॉलेजों को मिलेंगे सहायक प्राध्यापक

उच्च शिक्षा विभाग में भी इस साल बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। ट्रिपल आइटी को नई बिल्डिंग मिलेगी और डायरेक्टर मिलेगा। 300 प्रोफेसरों को प्रमोशन मिल सकता है। सरकारी स्कूलों में 500 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती होगी। सभी कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षा होगी।

दक्षता परीक्षा की आड़ में शिक्षकों की बर्खास्तगी मंजूर नहीं

शिक्षक अध्यापक संगठन ने आयुक्त लोक शिक्षण को सौंपा ज्ञापन, बताई समस्याएं

शहर प्रतिनिधि, भोपाल। दक्षता परीक्षा की आड़ में शिक्षकों की बर्खास्तगी किसी हाल में मंजूर नहीं की जाएगी। शिक्षकों की बर्खास्तगी की गई, तो प्रदेश भर में शिक्षक संयुक्त रुप से आंदोलन करेंगे। यह चेतावनी शिक्षक अध्यापक संगठन ने दी। शुक्रवार को संगठन के पदाधिकारी प्रमुख सचिव रश्मि शमी व आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत से नववर्ष पर सौजन्य भेंट करने पहुंचे थे। संगठन के पदाधिकारियों ने शिक्षकों की दक्षता परीक्षा निरस्त करने तथा दंड की कार्यवाही के स्थान पर शिक्षकों के प्रशिक्षण कराने एवं राज्य शिक्षा सेवा कैडर में व्याप्त विसंगतियों के निराकरण के संबंध में पीएस व आयुक्त से चर्चा की। दोनो अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि शिक्षकों पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। नए कैडर की सेवा शर्तों में जो विसंगतियां रह गई है, उनका निराकरण भी जल्द किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में आरिफ अंजुम, उपेंद्र कौशल, ओपी कटियार, अरविंद श्रीवास्तव, सुभाष शर्मा, शालिगराम चौधरी, जितेंद्र शाक्य, डैनी सूर्यवंशी, नीरज नायक सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे।

तीन व चार जनवरी को होगी परीक्षा : सत्र 2019-20 में दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम 40 फीसदी से कम आया है। उन स्कूलों के शिक्षकों की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दक्षता मूल्यांकन किया जा रहा है। इस परीक्षा में प्रदेश से 7 हजार 910 शिक्षक शामिल होंगे। इसमें शिक्षक किताब देखकर परीक्षा दे सकते हैं। इस बार मिडिल स्कूल के 6299 और हाई व हायर सेकंडरी के 1611 शिक्षकों के दक्षता का आंकलन होगा। परीक्षा तीन व चार जनवरी को होगी।

सोलह शिक्षकों को मिली थी अनिवार्य सेवानिवृत्ति : पिछले साल भी स्कूल शिक्षा विभाग ने दसवीं बोर्ड परीक्षा में 30 फीसदी से कम परीक्षा परिणाम लाने वाले स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा दो बार ली थी। दोबारा फेल होने पर प्रदेश के 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी।

अनुसूचित-जनजाति वर्ग के छात्रावासों के छात्रों को मिलेगी बढ़ी हुई राशि

भास्कर न्यूज | सतना

आदिम-जाति कल्याण विभाग ने अनुसूचित-जनजाति के छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की दर में वृद्धि की है। वर्ष 2020-21 में बालकों की छात्रवृत्ति 1300 रुपये और बालिकाओं के लिए 1340 रुपये प्रतिमाह की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई है। प्रदेश में अनुसूचित-जनजाति के छात्रावास और आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की दर प्रत्येक वर्ष मार्च में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस वर्ष बढ़ी हुई छात्रवृत्ति की दर एक जुलाई 2020 से प्रभावशील होगी।

आदिम जाति कल्याण के स्कूल खोलने के लिए दिशा–निर्देश जारी

आदेश

भोपाल। शिक्षा सत्र 2020-21 में आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नियमित रूप से निर्धारित समय तक के लिए संचालित होंगे। विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। यह माता-पिता की सहमति पर निर्भर करेगा।

ओपन बुक व ऑनलाइन पद्धति में उलझी परीक्षाएं

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने भले ही पिछले सत्र की परीक्षाएं जनरल प्रमोशन और ओपन बुक पद्धति से करवाई हो, लेकिन अब सत्र 2020-21 की सेमेस्टर परीक्षा के संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। विवि ओपन बुक और ऑनलाइन पद्धति में परीक्षा को लेकर उलझ गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी का कहना है कि सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन आना बाकी है। उसके बाद ही परीक्षा करवाई जा सकती है। लेकिन अगर जल्द ही गाइडलाइन नहीं आती है तो विश्वविद्यालय को सेमेस्टर परीक्षाओं के कार्यक्रम में फेरबदल करना होगा। परीक्षा में देरी न हो इसके लिए विभाग को विश्वविद्यालय ने पत्र भी लिखा दिया है।

चार करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के दायरे में लाएगी मोदी सरकार

पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए चलेगा अभियान

भोपाल (नप्र)। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 59 हजार करोड़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अनुसूचित जाति वर्ग के 60 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है, लेकिन मोदी सरकार ने अब चार करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के दायरे में लाने का फैसला किया है। देश के 1.36 करोड़ बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। मोदी सरकार स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए घर-घर संपर्क अभियान चलाएगी। आर्य ने संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि 1944 में अजा वर्ग के पोस्टमैट्रिक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई। उसके बाद देश में 57 साल और मध्यप्रदेश में 45 सालों तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं। आर्थिक तंगी और असुविधाओं के कारण अनुसूचित जाति के करोड़ों बच्चों ने पढ़ाई-लिखाई छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इसकी फिक्र नहीं की। देश में पहली बार मोदी सरकार ने इस बारे में सोचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारें सिर्फ इस वर्ग के बच्चों के साथ खेलती रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार के इस नए कदम से अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों का भविष्य संवरेगा और उनका जीवन बेहतर होगा। आर्य ने कहा कि मोदी सरकार जो 59 हजार करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अजा वर्ग के बच्चों को देने जा रही है, उसका 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी और 40 फीसदी हिस्सा राज्यों को देना होगा। राज्य सरकार पहले बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेगी और अपने हिस्से की रकम बच्चों के खातों में डालेगी, जिसके बाद केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि बच्चों के खातों में जमा कराएगी। केंद्र सरकार अपने हिस्से की छात्रवृत्ति में हर साल पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगी।

सीएम हाउस ने जेयू से मांगा बीएससी नर्सिंग की फर्जी मार्कशीट पर जवाब

ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जीवाजी विश्वविद्यालय (जेयू) से जारी हुई बीएससी नर्सिंग चतुर्थ वर्ष (परीक्षा जून 2019) की फर्जी मार्कशीट का मामला मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गया है। चार कार्य परिषद सदस्यों ने इस कांड की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय से की थी। कार्यालय से आए पत्र के बाद अब जेयू ने बिंदुवार जवाब बनाना शुरू कर दिया है।

जेयू से बीएससी नर्सिंग के उन विद्यार्थियों को पास की मार्कशीटें जारी की गई थीं, जो फेल थे। चार्टों में हेराफेरी करके ऐसा किया था। कार्य परिषद के खुलासे के बाद जेयू ने तीन सदस्यीय कमेटी से जांच कराई थी। इस कमेटी ने खानापूर्ति करके जेयू को रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन इस रिपोर्ट को खोला नहीं गया है। रिपोर्ट खुलवाने के लिए कार्य परिषद सदस्यों ने काफी दबाव डाला, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। उच्च शिक्षा मंत्री से भी शिकायत की। इसके बाद कार्य परिषद सदस्य शिवेन्द्र सिंह, अनुप अग्रवाल, मनेंद्र सोलंकी व संगीता चौहान ने मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत की। इस कांड की हकीकत से अवगत कराया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कलेक्टर के माध्यम से कुलसचिव से जवाब मांगा है। कुलसचिव आनंद मिश्रा का कहना है कि जवाब बनाया जा रहा है।

शिकायती पत्र में इन मुद्दों को उठाया

- जेयू के बीपीएड कोर्स को मान्यता नहीं है, लेकिन जेयू ने विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिए हैं। इससे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है।
- रिजल्ट जारी करने से पहले एक कमेटी उसकी जांच करती है। कमेटी होने के बाद भी फर्जी तरीके से रिजल्ट कैसे जारी हो गया।
- शासन ने किसी भी व्यक्ति को नगद भुगतान पर रोक लगाई है, लेकिन जेयू में नगद भुगतान किया जा रहा है। दिल्ली के वकील के नाम नगद पैसे दिए गए हैं।

- जेयू में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले कार्य परिषद की अनुमति नहीं ली जा रही है। करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं।

एमबीबीएस छात्रों ने परीक्षा देकर निजी कालेज को पहुंचाया फायदा

सीबीआई 7 जनवरी को पेश कर सकती है चालान

ग्वालियर। विशेष सत्र न्यायालय ने पीएमटी कांड के 11 आरोपितों का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपित पहले से ही एमबीबीएस कर रहे थे। फिर भी उन्होंने पीएमटी दी। निजी मेडीकल कालेज को फायदा पहुंचाने के लिए आखिर वक्त पर प्रवेश को निरस्त करा देते थे। उन्होंने शासन के साथ छल किया है। ऐसे आरोपितों को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। आरोपितों की ओर से तर्क दिया गया कि काउंसिलिंग में शामिल होने के बाद मेडीकल कालेज में प्रवेश के लिए निर्देशित किया गया है। सीबीआई 7 जनवरी को चालान पेश कर सकती है, उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया है। ऐसी स्थिति में कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

कोर्ट जमानत की शर्त लगाएगा, उसका पालन किया जाएगा। सीबीआई की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित पहले से पीएमटी पास कर एमबीबीएस में प्रवेश ले चुके थे, लेकिन 2011 की पीएमटी में बैठे।

रीवा छात्रवृत्ति घोटाला: 2 कर्मचारियों को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

भास्कर न्यूज. रीवा। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (अजाक) रीवा में हुए 2.10 करोड़ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में दो कर्मचारियों को कलेक्टर इलैय्या राजा टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संबंधितों से कलेक्टर ने आडिट रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पूछा है कि क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं शनिवार को एक कम्प्यूटर आपरेटर ने सरकारी खजाने में एक लाख की राशि जमा कराई है। इस तरह अभी तक गबन के 1, 78, 52,482 रुपए वसूले जा चुके हैं। कलेक्टर ने सहायक ग्रेड- 3 रामनरेश पटेल व कम्प्यूटर आपरेटर अनिल शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं एक अन्य मामले में सहायक ग्रेड -3 पटेल को दोषी पाया गया है। जिसके चलते उन्हे निलंबित किया जा चुका है। कलेक्टर का कहना है कि अगर 2.10 करोड़ के गबन मामले में विभागीय रूप से दोषी पाए जाते हैं, तो कार्रवाई को निलंबन के साथ जोड़ दिया जाएगा। साथ ही संबंधित के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई हो सकती है। अभी पूरे मामले की जांच जारी है।

ये है मामला • गत दिनों अजाक विभाग की आडिट रिपोर्ट आई थी। जिसमें विभागीय कर्मचारियों द्वारा 2.10 करोड़ का गबन का उल्लेख है। बताया गया है कि छात्रवृत्ति की राशि कर्मचारियों ने अपने व परिजनों के खाते में ट्रांसफर की है। रिपोर्ट में सहायक ग्रेड-3 रामनरेश पटेल के नाम का जिक्र है। कहा गया है कि रामनरेश पटेल, उनकी पत्नी सुमन सिंह, पुत्री सीमा कौशिक, पुत्र उदित सिंह और नीलेश कौशिक के नाम पर करीब 85.64 लाख की राशि ट्रांसफर की गई। मामला यहीं नहीं रूका है। बल्कि रिपोर्ट में संतोष कुमार पटेल का जिक्र है जो रामनरेश पटेल के भाई हैं। इनके खाते में भी 2.37 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसी तरह क्लर्क रामसुफल पटेल का भी जिक्र है। उनके व परिजनों के नाम 21.13 लाख रुपए की राशि हस्तांतरिक की गई है। बताया गया है कि रिपोर्ट में रामसुफल पटेल की पत्नी मालती, पुत्र राजनीश पटेल, पुत्र अवनीश पटेल के नाम राशि ट्रांसफर की गई है।

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट: 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं

जबलपुर। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2021 की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स अब परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की तरफ से जारी नोटिफिकेशन

के मुताबिक एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन 09 मई, 2021 को किया जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन यानी पेन-पेपर फॉरमेट में ईवनिंग स्लॉट यानी शाम तीन से पाँच बजे के बीच आयोजित होगी। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in के जरिए 31 मार्च, 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।

एग्जाम पैटर्न। परीक्षा में इंग्लिश, करेंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्नीक और लॉजिकल रीजनिंग और के 150 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएँगे। एग्जाम अथॉरिटी ने एडमिट कार्ड रिलीज होने को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। ऐसे में कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वह ऑफिशियल वेबसाइट पर समय -समय पर विजिट करते रहे है।

पहली से आठवीं के स्टूडेंट्स को घर जाकर वर्कशीट पहुंचा रहे शिक्षक

भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के करीब एक करोड़ विद्यार्थियों

शिक्षा

का वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों ने शुक्रवार को घर-घर जाकर वर्कशीट का वितरण शुरू कर दिया है। फरवरी में होने वाले वार्षिक मूल्यांकन में इसके नंबर जोड़े जाएंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र के नियंत्रक मूल्यांकन केपीएस तोमर के मुताबिक जनवरी में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों का मूल्यांकन छमाही और प्रतिभा पर्व एक साथ किया जाएगा। इसके लिए 15 जनवरी तक शिक्षक वर्कशीट का वितरण करेंगे।

आउटसोर्स कर्मचारियों को आयु सीमा से मुक्त रखने लिखा पत्र

भोपाल। एम्स अस्पताल में कार्यरत 700 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कार्यकाल तीन माह

एम्स

के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन प्रबंधन ने नया विज्ञापन भी जारी कर दिया है। इसमें नए कर्मचारियों की आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है। अस्पताल में पहले से जो कर्मचारी 8 या 9 साल से काम कर रहे हैं, उनकी आयु ज्यादा हो चुकी है। उनको आयु सीमा में छूट देने के लिए सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अस्पताल प्रबंधन को पत्र लिखा है।

यूजी-पीजी में अब तक 4,043 स्टूडेंट्स ने कराया वेरिफिकेशन

भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यूजी-पीजी की 4,73,452 सीटों के लिए अतिरिक्त छठवां राउंड चलाया जा रहा है। शनिवार को दस्तावेज सत्यापन का अंतिम दिन था, इसमें रजिस्टर्ड 4717 स्टूडेंट्स में से 4043 ने दस्तावेजों के सत्यापन करा लिए हैं। स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग के साथ 4 जनवरी को मेरिट लिस्ट जारी होगी। यह अतिरिक्त राउंड 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाए गए पांच राउंड में हुए एडमिशन के बाद भी कई कॉलेजों व छात्रों द्वारा एडमिशन नहीं होने की शिकायत की गई थी।

कॉलेज छात्राओं को बताया टैक्स और मैनेजमेंट का महत्व

संत नगर। संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज के वाणिज्य विभाग द्वारा 'ऐन ओवर व्यू एंड असेसमेंट-टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट' विषय पर वेबटॉक आयोजित किया गया।

मुख्य वक्ता डॉ. बासंती मैथ्यू मर्लिन मौजूद रहीं। प्राचार्य डॉ. डालिमा पारवानी ने कहा कि इससे छात्राओं को टैक्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। वर्तमान में छात्राएं इससे निश्चित ही लाभान्वित होंगी। मुख्य वक्ता डॉ. बासंती मैथ्यू मर्लिन ने टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की व्याख्या कर उसकी आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने टैक्स असेसमेंट प्रोसेस के बारे में बताते हुए छात्राओं को ई-टैक्सेशन से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। इस वेबटॉक में 100 छात्राएं पंजीकृत होकर लाभान्वित हुईं।

जिला स्तरीय रोजगार मेला 12 को, 24 कंपनियां आएंगी

ग्वालियर। जिला रोजगार कार्यालय (मॉडल कॅरियर सेंटर) द्वारा 12 जनवरी को जिला स्तरीय रोजगार मेला लगाया जायेगा। इस दिन यह मेला यहां बिरला नगर स्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रातः 11 बजे शुरू होगा। रोजगार मेले में लगभग दो दर्जन कंपनियां कैम्पस भर्ती करने आएंगीं।

उप संचालक जिला रोजगार कार्यालय श्रीमती प्रियंका कुलश्रेष्ठ ने बताया कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ग्वालियर, नव भारत फर्टिलाइजर लिमिटेड भोपाल, डैक्कन टेक्नोसेक्विटी एंड यूटिलिटी सर्विसेज प्रा.लि. इंदौर, ईगल सिक्योरिटी सर्विस शिवपुरी, स्टार हैल्थ इंश्योरेंस ग्वालियर एवं एलआईसी ग्वालियर द्वारा रोजगार मेले में आने की सहमति दी जा चुकी है। इसके अलावा अन्य कंपनियों से भी सतत संपर्क जारी है। निजी कंपनियों में नौकरी करने के इच्छुक आवेदकों से रोजगार मेले में शैक्षणिक योग्यता के मुल प्रमाण-पत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ लेकर आने की अपील की गई है। साथ ही नियोजक एवं कौशल प्रदाता संस्थाओं को भी इस मेले में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा खुला आमंत्रण दिया गया है।

नैक में 2.5 अंक होने से लगा प्रतिबंध, प्रवेश कराने चाहिए 3.26 अंक

UGC ने BU के पत्राचार से प्रवेश पर लगाई रोक

प्रदेश टुडे संवाददाता, भोपाल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नैक का ए-प्लस एग्रेडेशन नहीं होने पर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पत्राचार विभाग में स्नातक के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। अब बीए और बीकॉम के प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं होंगे, लेकिन वर्तमान में द्वितीय और तीसरे वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षाएं अगले माह में जरूर हो सकेंगी। बीयू नैक के ए प्लस के एग्रेडेशन हासिल करने में अक्षम साबित हुआ है। इसलिए यूजीसी ने बीयू के पत्राचार विभाग के सत्र 2020-21 में स्नातक के कोर्स बीए और बीकॉम नये प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। प्रवेश की पात्रता लेने बीयू को नैक का ए प्लस होना अनिवार्य है। इसके तहत देशभर के सभी विश्वविद्यालयों को नैक में 3.26 अंक हासिल करना जरूरी है। जबकि बीयू को नैक में 2.5 अंक से बी एग्रेडेशन प्राप्त है। बीयू कुलपति आरजे राव को पत्राचार प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने नैक में 3.26 अंक हासिल करने होंगे, जिसके लिए एप्लीकेशन किए जा रहे हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए बीयू ए एग्रेडेशन हासिल कर सकता है, लेकिन ए प्लस के लिए 3.26 लेने काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीयू में प्रोफेसरों के साथ कई संसाधानों का अभाव है।

डिग्री होगी पूरी, सिर्फ डिप्लोमा में होगा प्रवेश

नैक से 3.26 हासिल नहीं करने की दशा में विवि डिग्री में प्रवेश नहीं दे पाएंगे, लेकिन वह डिप्लोमा कोर्स संचालित जरूर कर सकेंगे। वर्तमान में द्वितीय और तृतीय वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे। बीयू बीए और बीकाम की परीक्षाएं अगले माह में लेगा। क्योंकि अभी पूरक परीक्षाओं के रिजल्ट आना शेष है। जैसे ही उनके रिजल्ट जारी हो जाते है। बीयू ओपन बुक से द्वितीय और तीसरे वर्ष की परीक्षाएं कराएगा। इसका टाइम टेबिल बीयू आईओडी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

प्रदेश के सभी विवि होंगे बाहर

डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विवि भी नैक की ए ग्रेड की सूची में काबिज नही हैं, जिसके कारण उसके पत्राचार के प्रवेश भी प्रतिबंधित हो चुके हैं। यही स्थिति राज्य के अन्य विवि की रहेगी। उन्हें पत्राचार के प्रथम वर्ष सत्र 2021-22 में प्रवेश देना है, तो उन्हें यूजीसी से नैक से 3.26 अंक हासिल करना होंगे। वही भोज विवि का अभी तक नैक नहीं हो सका है, जिसके कारण उसके कोर्स संचालित हो रहे हैं। इसलिए गत वर्ष उनके कुछ कोर्स यूजीसी ने बंद कर दिए थे।

SPS से IPS प्रमोशन के लिए तीस पद ज्यादा मांगे

370 होंगे IPS के पद, IG कॉडर में चार पोस्ट की कटौती

मध्यप्रदेश डीजी ट्रेनिंग और आईजी कॉडर के चार पद समाप्त हो जाएंगे। वहीं आईपीएस कॉडर में 39 नए पद बढ़ेंगे। वर्तमान में एमपी में 166 कॉडर पोस्ट है जो बढ़कर 200 हो जाएंगी। इससे एक्स कॉडर पोस्ट मिलाकर प्रदेश में आईपीएस अफसरों के लिए कुल 370 पद हो जाएंगे। नये कॉडर रिव्यू में राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 82 से बढ़ाकर 112 प्रस्तावित की गई है। इसे मंजूरी मिली तो राज्य पुलिस सेवा के 95 और 96 बैच के अफसरों को भी इसी साल पदोन्नति मिल सकेगी।

ब्यूरो, भोपाल

गृह विभाग ने एमपी का आईपीएस कॉडर रिव्यू प्रस्ताव केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद डीओपीटी आदेश जारी करेगा। वर्तमान में 116 कॉडर पोस्ट है। इनमें डीजी के लिए पांच कॉडर पोस्ट पर दुगने याने दस अफसर डीजी बन सकते है। असके अलावा एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी के लिए कुल 36 एक्स कॉडर पोस्ट है। इनको मिलाकर वर्तमान में आईपीएस के लिए कुल 395 पद है। मौजूदा कॉडर रिव्यू को मंजूरी मिलती है तो कॉडर और एक्स कॉडर पोस्ट मिलाकर प्रदेश में कुल 370 पद आईपीएस के लिए हो जाएंगे। आईजी के लिए वर्तमान में 36 कॉडर पोस्ट है। इनमें से चार कम करने और एसडीआरएफ में एक पद बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है।

डीजी और आईजी के ये पांच पद होंगे समाप्त

डीजी प्रशिक्षण पीएचक्यू और होमगार्ड जबलपुर,पीटीआरआई, जेएनपीए सागर और आरएपीटीसी इंदौर मे आईजी के चार पद सरेण्डर किये जाएंगे। एडीजी टेक्नीकल एण्ड फायर सर्विसेस मे से एडीजी फायर सर्विसेस अलग कर डीजी ट्रेनिंग प्रशिक्षण का नया पद प्रस्तावित किया गया है। इस तरह डीजी की कॉडर पोस्ट पांच से बढ़कर छह हो जाएगी। एक्स कॉडर की छह पोस्ट मिलाकर कुल बारह अफसर डीजी बन सकेंगे। एडीजी के लिए कुल आठ नये पद मांगे गए है। एडीजी की वर्तमान मे मध्यप्रदेश में सोलह कॉडर पोस्ट है, आठ नऐ पद मिलने पर एडीजी के लिए कुल 24 कॉडर पोस्ट हो जाएगी। एडीजी के लिए जो नई कॉडर पोस्ट मांगी गई है उनमे एंटी नक्सल ऑपरेशन, सायबर क्राइम, नारकोटिक्स, एसटीएफ के लिए एक-एक पोस्ट मांगी गई है।

डीआईजी के लिए तीस कॉडर पोस्ट

डीआईजी की 22 कॉडर पोस्ट है इसमें प्रस्तावित आठ पद बढ़ने पर तीस कॉडर पोस्ट हो जाएंगी। जो नये पद मांगे गए है वे एसएएफ हेडक्वार्टर, पीएचक्यू प्रोविजनिंग, महिला अपराध के लिए, सलेक्शन पीएचक्यू, पर्सनल पीएचक्यू, प्लानिंग पीएचक्यू, एंटी नक्सल आपरेशन और एक पद डब्ल्यू ए पीएचक्यू के लिए मांगा गया है।

एसपी के लिए होगी 107 कॉडर पोस्ट

वर्तमान में एसपी के लिए कुल 87 कॉडर पोस्ट है। बीस नई कॉडर पोस्ट और मांगी गई है। इनको मिलाकर एसपी के लिए कुल 109 कॉडर पोस्ट हो जाएंगी। सायबर क्राइम के लिए तीन नये पद मांगे गए है। एसटीएफ का भी विस्तार राज्य सरकार करना चाहती है इसके लिए दो नई कॉडर पोस्ट मांगी गई है। इसके अलावा एटीएस मे दो, पीटीएस मे एक, ईओडब्ल्यू में चार, लोकायुक्त मे चार, एसएफ मंडल के लिए एक, निवाडी के लिए एक और पीएचक्यू के लिए दो नये पद मांगे गए है।

ड्राप आउट स्टूडेंट्स को वापस लाने सरकार चलाएगी अभियान-आर्य

भोपाल। भाजपा अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने एससी वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति में वृद्धि के केंद्र सरकार के फैसले को सराहनीय बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार इस वर्ग के ड्राप आउट बच्चों को मुख्य धारा में लाने का अभियान चलाएगी। इसको लेकर वे सरकार से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि इसको हर स्तर पर मानीटरिंग भी की जाएगी। आर्य ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा में कहा कि अब तक सिर्फ 60 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा था जो अब चार करोड़ स्टूडेंट्स को लाभ दिलाने वाला होगा। इससे स्कूलों में एससी वर्ग के बच्चों की संख्या में वृद्धि होगी। आर्य ने कहा कि 1954 के बाद किसी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। केंद्र सरकार का यह कदम ऐतिहासिक साबित होगा।

दसवीं-बारहवीं में चालीस फीसदी से कम परिणाम देने वाले शिक्षक किताब देखकर देंगे परीक्षा

प्रदेश के आठ हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आज साबित करनी होगी अपनी योग्यता

शहर प्रतिनिधि, भोपाल । प्रदेश के आठ हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को रविवार-सोमवार को अपनी योग्यता साबित करना होगी। दसवीं-बारहवीं में चालीस फीसदी से कम परिणाम देने वाले इन शिक्षकों की 3 जनवरी रविवार व 4 जनवरी सोमवार को परीक्षा होगी। यह शिक्षक किताब देखकर परीक्षा देंगे। किताब देखने के बाद भी शिक्षक फेल हुए, तो दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें भी फेल होने पर इन शिक्षकों को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। सत्र 2019-20 में दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम 40 फीसदी से कम आया है। उन स्कूलों के शिक्षकों की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दक्षता मूल्यांकन किया जा रहा है। इस परीक्षा में प्रदेश से 7 हजार 910 शिक्षक शामिल होंगे। इसमें शिक्षक किताब देखकर परीक्षा दे सकते हैं। इस बार मिडिल स्कूल के 6299 और हाई व हायर सेकेंडरी के 1611 शिक्षकों के दक्षता का आंकलन होगा। हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा 3 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगी। वहीं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा 4 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगी। इसमें सभी विषयों के शिक्षकों की परीक्षा होगी। राजधानी में परीक्षा केंद्र एक्सीलेंस स्कूल होगा।

सोलह शिक्षकों को मिली थी अनिवार्य सेवानिवृत्ति : पिछले साल भी स्कूल शिक्षा विभाग ने दसवीं बोर्ड परीक्षा में 30 फीसदी से कम परीक्षा परिणाम लाने वाले स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा दो बार ली थी। दोबारा फेल होने पर प्रदेश के 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। गौरतलब है कि इस बार शिक्षक संगठन परीक्षा विरोध कर रहे है। शिक्षक संगठनों को विभाग के आला अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया है कि शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी जाएगी। हलांकि पिछले परीक्षा के समय भी शिक्षक संगठनों को यही आश्वासन मिला था। बावजूद इसके शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई।

जिले के 67 शिक्षक परीक्षा में होंगे शामिल: जिले से 67 शिक्षक परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी के 15 शिक्षकों की परीक्षा रविवार को होगी। जबकि मिडिल स्कूल के 52 शिक्षकों की परीक्षा सोमवार को होगी। इसमें शासकीय उमावि कालापानी, शासकीय उमावि महात्मा गांधी, शासकीय उमावि उबेदिया, शासकीय बालक उमावि नूतन सुभाष, शासकीय उमावि तूमड़ा, शासकीय हाईस्कूल आरिफ नगर, शासकीय हाईस्कूल बाग उमरावदुल्हा आदि बैरसिया क्षेत्र के भी तीन स्कूल शामिल हैं। राजधानी के उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा केंद्र होगा। इस परीक्षा में भिंड के सबसे ज्यादा 505 शिक्षक शामिल होंगे। इसके बाद बैतूल के 231, अलिराजपुर के 182, अशोकनगर के 119 शिक्षक दक्षता मूल्यांकन में शामिल होंगे। परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को उसी दिन कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। उपयुक्त कारण होने पर (कोरोना संक्रमण इत्यादि) अनुपस्थित शिक्षकों की पुन: परीक्षा ली जाएगी। इस हेतु अलग से परीक्षा तिथि की सूचना दी जाएगी।

गोपनीय रखा जाएगा परिणाम

शिक्षकों की परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी दिन किया जाएगा। परीक्षा परिणाम गोपनीय रखा जाएगा। परीक्षा परिणाम कम होने पर शिक्षकों को दो माह की अवधि दक्षता सुधार के लिए दी जाएगी। जिला स्तर के इन शिक्षकों का ऑनलाईन प्रशिक्षण भी किया जाएगा। इसके बाद मार्च के पहले सप्ताह में दोबारा परीक्षा होगी। इसमें भी शिक्षक फेल होते है, तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी सकती है।

शिक्षक संगठनों ने कहा- परीक्षा की आड़ में बर्खास्तगी बर्दाश्त नहीं

प्रदेश के 7910 शिक्षकों की दक्षता परीक्षा आज व कल, किताब देखकर हल कर सकेंगे प्रश्न

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

मो.नं. 9893231237

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 40 फीसदी से कम रिजल्ट वाले 7910 शिक्षकों की दक्षता जांचने के लिए रविवार व सोमवार को परीक्षा होगी। कई शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि दक्षता परीक्षा से डर नहीं लगता है, लेकिन इसकी आड़ में शिक्षकों की बर्खास्तगी मंजूर नहीं की जाएगी। ऐसा हुआ, तो हम लोग प्रदेशभर में आंदोलन करेंगे।

संगठन के पदाधिकारी प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी व आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत से नववर्ष पर सौजन्य भेंट करने पहुंचे थे। उन्होंने दक्षता परीक्षा निरस्त करने तथा दंड के स्थान पर शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं राज्य शिक्षा सेवा कैडर में व्याप्त विसंगतियों के निराकरण के संबंध में चर्चा की। दोनों अधिकारियों ने

आश्वस्त किया कि शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। नए कैडर की सेवा शर्तों में जो विसंगतियां हैं, उनका निराकरण किया जाएगा।

सत्र 2019-20 में दसवीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जिन स्कूलों का रिजल्ट 40 फीसदी से कम आया है, उनके शिक्षकों दक्षता जांची जा रही है। परीक्षा में प्रदेश से 7,910 शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षक किताब देखकर परीक्षा दे सकते हैं। इसमें मिडिल स्कूल के 6299 और हाई व हायर सेकंडरी के 1611 शिक्षकों के दक्षता का आंकलन होगा।

16 शिक्षक हुए थे बर्खास्त

पिछले साल भी स्कूल शिक्षा विभाग ने दसवीं बोर्ड परीक्षा में 30 फीसदी से कम परीक्षा परिणाम लाने वाले स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा दो बार ली थी। दोबारा फेल होने पर प्रदेश के 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी।

भोपाल के 67 शिक्षक

परीक्षा में भोपाल के 67 शिक्षक शामिल होंगे। भिंड के 505, बैतूल के 231, अलिराजपुर के 182, अशोकनगर के 119 शिक्षक शामिल होंगे।

गैर हाजिर तो कार्रवाई

परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को उसी दिन कारण बताओ नोटिस जारी कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उपयुक्त कारण होने पर (कोरोना संक्रमण आदि) अनुपस्थित शिक्षकों की पुन: परीक्षा ली जाएगी।

चार करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के दायरे में लाएगी मोदी सरकार

पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए चलेगा अभियान

भोपाल (नप्र)। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 59 हजार करोड़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अनुसूचित जाति वर्ग के 60 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है, लेकिन मोदी सरकार ने अब चार करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के दायरे में लाने का फैसला किया है। देश के 1.36 करोड़ बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। मोदी सरकार स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए घर-घर संपर्क अभियान चलाएगी। आर्य ने संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि 1944 में अजा वर्ग के पोस्टमैट्रिक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई। उसके बाद देश में 57 साल और मध्यप्रदेश में 45 सालों तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं। आर्थिक तंगी और असुविधाओं के कारण अनुसूचित जाति के करोड़ों बच्चों ने पढ़ाई-लिखाई छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इसकी फिक्र नहीं की। देश में पहली बार मोदी सरकार ने इस बारे में सोचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारें सिर्फ इस वर्ग के बच्चों के साथ खेलती रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार के इस नए कदम से अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों का भविष्य संवरेगा और उनका जीवन बेहतर होगा। आर्य ने कहा कि मोदी सरकार जो 59 हजार करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अजा वर्ग के बच्चों को देने जा रही है, उसका 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी और 40 फीसदी हिस्सा राज्यों को देना होगा। राज्य सरकार पहले बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेगी और अपने हिस्से की रकम बच्चों के खातों में डालेगी, जिसके बाद केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि बच्चों के खातों में जमा कराएगी। केंद्र सरकार अपने हिस्से की छात्रवृत्ति में हर साल पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगी।

सरकारी स्कूलों के आठ हजार शिक्षक आज साबित करेंगे अपनी योग्यता

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपनी योग्यता का परिचय दक्षता मूल्यांकन परीक्षा के जरिए देंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से रविवार और सोमवार को शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है।

सत्र 2019-20 में दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम 40 फीसद से कम आया है। उन स्कूलों के शिक्षकों का दक्षता मूल्यांकन किया जा रहा है। इस परीक्षा में प्रदेश से 7 हजार 910 शिक्षक शामिल होंगे। हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा रविवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगी। वहीं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा 4 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगी। इन्हें 100 नंबर का पेपर तीन घंटे में किताब देखकर देना होगा। शिक्षकों को 100 में से 48 अंक लाना होगा। इससे कम अंक लाने पर फेल की श्रेणी में आएंगे। फेल हुए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तीन माह बाद फिर से दोबारा परीक्षा होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल परीक्षा में फेल हुए 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। जिले से 60 से अधिक शिक्षक परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें मिडिल के 52 और हायर सेकेंडरी के 14 शिक्षक हैं। राजधानी के शिवाजी नगर स्थित सुभाष उत्कृष्ट उमावि में यह परीक्षा आयोजित होगी।

दक्षता परीक्षा आज • किताब देखकर परीक्षा देंगे शिक्षक

भास्कर न्यूज. सतना

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में शून्य से 40 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले हाई स्कूल तथा हायर सेकंड्री स्कूल के शिक्षकों की दक्षता परीक्षा रविवार को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की जा रही है। शनिवार को परीक्षा में नियुक्त किए जा रहे पर्यवेक्षकों की ज्वाइनिंग परीक्षा केन्द्र में कराई गई। परीक्षा के लिए 20 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

यह परीक्षा शिक्षकों को किताब देखकर देनी है। हाल ही में छात्रों ने भी किताब देखकर ही परीक्षा दी थी। विभाग से जुड़े जानकारों का कहना है कि अगर शिक्षक पठन-पाठन से जुड़ा है तो वह किताब देखकर प्रश्न पत्र हल कर लेगा। बीते वर्ष इसी तरह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 4 शिक्षक फेल हुए थे, जिन्हें विभाग द्वारा बाद में बर्खास्त कर दिया गया था। इस परीक्षा में 44 शिक्षक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के शामिल होंगे।

माध्यमिक के शिक्षकों का परीक्षण कल

हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी के कैचमेंट एरिया में आने वाली माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों की परीक्षा सोमवार को दोपहर 12 बजे से एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित होगी। इस परीक्षा में 317 शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षकों को निर्धारित समय में उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित होने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ-साथ उन्हें अपने साथ फोटोयुक्त आईडी कार्ड-पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।

उसी दिन होगा मूल्यांकन

जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार परीक्षा के उपरांत मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। एक्सीलेंस प्राचार्य इन उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी दिन पूर्ण कराने के बाद अपनी रिपोर्ट लोक शिक्षण संचालनालय को भेजेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षकों की दक्षता परीक्षण के लिए प्रश्न पत्र जिला शिक्षा अधिकारी की आईडी में उसी दिन भेजे जाएंगे, जिनका प्रिंट तैयार कर शिक्षकों को वितरित किया जाएगा।

29 सरकारी स्कूलों में जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा

जबलपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय बरगी की 2021 में आयोजित होने वाली 6वीं और 9वीं प्रवेश परीक्षा को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने 29 सरकारी स्कूल के प्राचार्यों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्यों को पत्र भेजकर कहा कि 2021 में बरगी नवोदय विद्यालय की परीक्षा होना है इसके लिए 24 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों को परीक्षा केंद्र तब बनाया जाएगा, जब इन स्कूलों के प्राचार्य सहमति देंगे।

प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन 10 अप्रैल 2021 को दिन के 11.30 बजे से होगा। यह परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी। परीक्षा केंद्र नवोदय विद्यालय ही होंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2020 थी।

24 फरवरी को 9वीं की प्रवेश परीक्षा: जवाहर नवोदय विद्यालय बरगी में प्रवेश की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 24 फरवरी को 9वीं प्रवेश परीक्षा होगी इसके लिए पं.लाा शंकर झा, व्हीकल स्टेट रांझी हाईस्कूल, शासकीय उमावि मेडिकल, बरगी शासकीय स्कूल, रानी दुर्गावती कन्या गढ़ा स्कूल को परीक्षा केंद्र के लिए चयन किया गया है। हालांकि इन प्राचार्यों की सहमति के बाद ही स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा।

10 अप्रैल को कक्षा 6वीं के लिए होगी प्रवेश परीक्षा: 10 अप्रैल को कक्षा 6वीं में प्रवेश की परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए प्रत्येक विकासखंड के शासकीय स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कुल 24 सरकारी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय देगा नौकरी

31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को 'सलाहकार' बनाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली स्व.स.से.

केंद्र सरकार अपने पूर्व कर्मियों पर खासी मेहरबान है। अधिकांश केंद्रीय मंत्रालय और विभाग अब स्थायी नौकरी का विज्ञापन देने से बच रहे हैं।

'सलाहकार' के नाम से सेवानिवृत्त लोगों को नौकरी दी जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सह सचिव से लेकर सेक्शन अफसर तक के ऐसे अधिकारी जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं, को वर्ष 2021 के पहले ही दिन नई नौकरी का प्रस्ताव दे दिया है। इन्हें गृह मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। खास बात है कि सलाहकार लगने वालों से काम खूब लिया जाएगा, यह बात केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दी है। सुबह तय समय से पहले बुला सकते हैं तो वहीं रात को घर जाने में देरी भी हो सकती है।

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में विदेशी छात्रों को मिलेगा प्रवेश

भोपाल निप्र। अब प्रदेश के सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालयों में विदेशी छात्र भी बीएएमएस की डिग्री कर सकेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय भारत सरकार की सहमति पर निर्णय लिया गया है। विदेशी छात्रों के लिए सबसे पहले पं खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद कॉलेज भोपाल में एक सीट व शासकीय आयुर्वेद कॉलेज ग्वालियर में पांच सीटें आरक्षित रखी गयी हैं। फिलहाल 1200 आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी आयुष यूजी डिग्री सीटों के लिए काउंसलिंग जारी है और 7 जनवरी को सीट आवंटित होंगी। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में कुल 7 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय संचालित हैं। आयुष मेडिकल एसोसिएशन डॉ. राकेश पाण्डेय का कहना है कि आयुर्वेद कॉलेजों में विदेशी छात्रों के अध्ययन-अध्यापन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद की महत्ता बढ़ेगी। संभावना है कि देशभर के सभी आयुर्वेद कॉलेजों में विदेशी छात्र पढ़ते हुए दिखेंगे।

माशिम की हेल्पलाइन में विद्यार्थियों की गुहार, स्कूल तो खुल गए कोर्स कैसे पूरा होगा

शंका समाधान के लिए विद्यार्थी ले रहे हेल्पलाइन का सहारा

सतना, (नव स्वदेश)। मैडम स्कूल तो खुल गए लेकिन पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई है। फरवरी तक कोर्स पूरा होने की संभावना भी नहीं है तो क्या मार्च में ही परीक्षा होगी, परीक्षा में कैसे पैर्टन का पेपर आएगा। इस बार भी पिछले वर्षों के पेपर से तैयारी करें या नहीं, कोर्स कैसा कम किया गया है, कुछ इस तरह के प्रश्न माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिम की हेल्पलाइन में विद्यार्थी पूछ रहे हैं। इस सत्र में विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाए हैं। 10वीं व 12वीं की नियमित कक्षाएं अब शुरू हुई हैं। इस कारण कोरोना संक्रमण काल में विद्यार्थियों ने शंका समाधान के लिए मंडल की हेल्पलाइन का सहारा लिया।

दोगुना काल पहुंचे

हर साल की अपेक्षा इस साल हेल्पलाइन में दोगुना कॉल आए हैं। इसमें परीक्षा से संबंधित सवाल अधिक पूछे जा रहे हैं। हेल्पलाइन में प्रदेश भर से करीब दो लाख 35 कॉल विद्यार्थियों ने किए। हर रोज करीब 800 से 900 कॉल आ रहे हैं। सतना जिले से भी करीब 4 हजार से अधिक कॉल पहुंचे हैं। हेल्पलाइन में इस बार अभिभावकों के भी काफी कॉल आए। अभिभावक भी परीक्षा से संबंधित सवाल कर रहे हैं।

18 काउंसलर करते हैं मदद

मंडल ने तीन शिफ्ट में छह-छह काउंसलर को रखा है। विद्यार्थियों की काउंसिलिंग के लिए 18 काउंसलर, मनोवैज्ञानिक हैं, जो विद्यार्थियों के सवाल के जबाव देते हैं। साथ ही 120 से अधिक विषय विशेषज्ञ भी सवालों के जबाव दे रहे हैं। अब परीक्षा नजदीक है तो विद्यार्थी विषय से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्याए मानसिक तनाव से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न हेल्पलाइन नंबर पर पूछ सकते हैं।

एमएलबी स्कूल में जेडी की दबिश, गायब मिले 21 शिक्षक

भास्कर न्यूज. **सतना**

शहर के सबसे पुरानी कन्या शालाओं में शुमार महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का शनिवार को संयुक्त संचालक नीरव दीक्षित ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें स्कूल के 21 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। बताया गया कि स्कूल में व्यापक अनियमितताएं भी देखने को मिली हैं। जानकारी के मुताबिक जेडी को प्रभारी प्राचार्य द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। जब उपस्थिति पंजी मांगी गई तो उसे लाने में सवा 11 बजा दिया गया, इसके बाद भी 21 शिक्षक अनुपस्थित रहे। विद्यालय में टाइम टेबल तो कक्षा-9 से 12वीं तक का बनाया गया है, मगर कक्षाएं 10वीं और 12वीं की ही संचालित हो रहीं हैं उसमें भी छात्र संख्या बहुत कम है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कम किए गए पाठ्यक्रम की भी जानकारी छात्राओं को नहीं दी गई है, जिसको लेकर जेडी ने नाराजगी व्यक्त की है।

शिक्षकों की शिकायतों का निवारण होगा

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। अव प्रदेशभर के शिक्षकों, कर्मचारियों की शिकायतों का एक माह के अंदर ऑनलाइन निवारण होगा। शिक्षकों व कर्मचारियों को आवेदन लेकर विभाग के अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक ऑनलाइन सिस्टम परिवेदना निवारण प्रवंधन प्रणाली शुरू की है। यह विभाग के एम शिक्षा मित्र एप पर एक नया ऑप्शन होगा।

इस संवंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं। अगर एक माह के अंदर शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया तो इसके लिए

राहत

- स्कूल शिक्षा विभाग ने परिवेदना निवारण संबंधी आदेश जारी किए
- ऑनलाइन तरीके से एक महीने में दूर होगी समस्या

संवंधित कार्यालय एवं कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारी होंगे। इस आदेश यह भी लिखा है कि अव मैन्युअल आवेदन को नहीं लिया जाएगा। अव ब्लॉक या जिला कार्यालय में चक्कर नहीं काटने होंगे और न ही किसी अन्य शिकायत पोर्टल पर जाने की आवश्यकता होगी। इसमें एक निश्चित समय सीमा में संवंधित द्वारा दिए गए शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। विभाग के अंर्तगत कार्यरत एवं सेवानिवृत ऐसे शिक्षक व कर्मचारी जिनका एजुकेशन पोर्टल का यूनिक आइडी जनरेटेड है। विभाग से संवंधित स्वयं की समस्याओं के वारे में शिकायत ऑनलाइन रूप से शिक्षा पोर्टल या एम शिक्षा मित्र एप पर दर्ज करा सकेंगे। शिकायत का पंजीयन क्रमांक एवं शिकायत दर्ज होने संवंधी जानकारी शिकायतकर्ता के मोवाइल पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। आवेदक के लिए ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिसका प्रिंट आउट भी मिलेगी।

अजा के शत-प्रतिशत बेटे-बेटियों को शिक्षित करेगी मोदी सरकार

छात्रवृत्ति में 54 गुना बढोत्तरी, भाजपा अजा मोर्चा ने माना प्रधानमंत्री का आभार

विशेष संवाददाता ■ भोपाल

1944 में अजा वर्ग के पोस्टमैट्रिक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई। देश में 57 साल और मध्यप्रदेश में 45 सालों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं। आर्थिक तंगी और सुविधाओं के अभाव में अनुसूचित जाति के करोड़ों बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इसकी चिंता नहीं की। कांग्रेस सालों तक अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 59 हजार करोड़ कर दिया है। अजा वर्ग के बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में केन्द्र सरकार की इस पहल के लिए इस अभूतपूर्व पहल के लिए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं उनकी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता है।

यह बात अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह आर्य ने शनिवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कही। श्री आर्य ने बताया कि वर्तमान में अजा वर्ग के 60 लाख बच्चों को यह छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन अब मोदी सरकार इस वर्ग के 4 करोड़ बच्चों को छात्रवृत्ति के दायरे में लाएगी। इसके लिए केन्द्र सरकार विगत वर्षों में विद्यालय छोड़ चुके 1.36 करोड़ बच्चों को पुनः विद्यालय प्रवेश के लिए घर-घर संपर्क अभियान चलाएगी। श्री आर्य ने बताया कि मोदी सरकार जो 59 हजार करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अजा वर्ग के बच्चों को देने जा रही है, उसका 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी तथा 40 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को देना होगा। राज्य सरकार पहले बच्चों का पंजीयन करेगी और अपने हिस्से की रकम बच्चों के खातों में डालेगी, इसके बाद केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि बच्चों के खातों में जमा कराएगी। उन्होंने कहा कि 59 हजार करोड़ की इस छात्रवृत्ति में अगले पांच सालों तक केंद्र सरकार हर साल अपने हिस्से में 5 प्रतिशत की वृद्धि करेगी। इससे धीरे-धीरे राज्यांश भी घटता जाएगा।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इस पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी भी करेगी, ताकि अजा वर्ग का कोई और बच्चा छात्रवृत्ति न मिलने या देर से मिलने के कारण पढ़ाई छोड़ने पर विवश न हो। पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार की जनजातीय कल्याण विभाग की मंत्री सुश्री मीना सिंह एवं अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सूरज कैरो, विधायक सुभाष वर्मा, मोर्चा जिला अध्यक्ष जसवंत राव भी उपस्थित रहे।

कक्षा 1 से 8 वीं के विद्यार्थियों का वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट आधारित होगा

सतना (नव स्वदेश)। प्रदेश में शासकीय शालाओं में कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों का मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर होगा। आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र लोकेश कुमार जाटव ने बताया कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को वर्कशीट दी जाएगी। इसके आधार पर उनका अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थियों का अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन जनवरी माह में एवं वार्षिक मूल्यांकन फरवरी एवं मार्च में किया जाएगा।

शालाओं से अभ्यास पुस्तिका दी जायेगी

राज्य शिक्षा केंद्र ने माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी शासकीय शालाओं में शिक्षण सत्र 2020 -21 में कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक मूल्यांकन (प्रतिभा पर्व) एवं वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कक्षा पहली एवं दूसरी के बच्चों को शालाओं से ही अभ्यास पुस्तिका दी जाएगी जिसके अंत में वर्कशीट होगी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय के प्रश्न होंगे। कक्षा तीसरी से आठवीं तक के बच्चों को दी जाने वाली वर्कशीट में कौशल आधारित प्रश्न और प्रोजेक्ट वर्क होगा। वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर और प्रोजेक्ट वर्क लिखने के लिए स्थान रहेगा। वर्कशीट में 60 प्रतिशत लिखित एवं 40 प्रतिशत अंक प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट वर्क में छात्रों से कोई मॉडल नहीं बनवाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट वर्क घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों से पूछ कर पूरे किए जा सकेंगे। विद्यार्थियों का अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन 20 से 30 जनवरी के मध्य एवं वार्षिक मूल्यांकन 15 से 28 फरवरी और 10 से 20 मार्च के बीच किया जाएगा। परीक्षाफल का निर्धारण अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। हमारा घर-हमारा विद्यालय अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों के सह-शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन कर ग्रेड का निर्धारण करेंगे। इन परीक्षाओं का संचालन करते हुए कोविड-19 संक्रमण से बचाव के नियत सुरक्षा मापदंडों और गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।

आउटसोर्स कर्मचारियों को आयु सीमा से मुक्त रखने लिखा पत्र

एम्स

भोपाल। एम्स अस्पताल में कार्यरत 700 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कार्यकाल तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन प्रबंधन ने नया विज्ञापन भी जारी कर दिया है। इसमें नए कर्मचारियों की आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है। अस्पताल में पहले से जो कर्मचारी 8 या 9 साल से काम कर रहे हैं, उनकी आयु ज्यादा हो चुकी है। उनको आयु सीमा में छूट देने के लिए सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अस्पताल प्रबंधन को पत्र लिखा है।

आदिम जाति कल्याण के स्कूल खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी

आदेश

भोपाल। शिक्षा सत्र 2020-21 में आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नियमित रूप से निर्धारित समय तक के लिए संचालित होंगे। विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। यह माता-पिता की सहमति पर निर्भर करेगा।

पहली से आठवीं के स्टूडेंट्स को घर जाकर वर्कशीट पहुंचा रहे शिक्षक

शिक्षा

भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के करीब एक करोड़ विद्यार्थियों का वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों ने शुक्रवार को घर-घर जाकर वर्कशीट का वितरण शुरू कर दिया है। फरवरी में होने वाले वार्षिक मूल्यांकन में इसके नंबर जोड़े जाएंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र के नियंत्रक मूल्यांकन केपीएस तोमर के मुताबिक जनवरी में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों का मूल्यांकन छमाही और प्रतिभा पर्व एक साथ किया जाएगा। इसके लिए 15 जनवरी तक शिक्षक वर्कशीट का वितरण करेंगे।

यूजी-पीजी में अब तक 4,043 स्टूडेंट्स ने कराया वेरिफिकेशन

भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यूजी-पीजी की 4,73,452 सीटों के लिए अतिरिक्त छठवां राउंड चलाया जा रहा है। शनिवार को दस्तावेज सत्यापन का अंतिम दिन था, इसमें रजिस्टर्ड 4717 स्टूडेंट्स में से 4043 ने दस्तावेजों के सत्यापन करा लिए हैं। स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग के साथ 4 जनवरी को मेरिट लिस्ट जारी होगी। यह अतिरिक्त राउंड 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाए गए पांच राउंड में हुए एडमिशन के बाद भी कई कॉलेजों व छात्रों द्वारा एडमिशन नहीं होने की शिकायत की गई थी।

मंत्री ने कहा- छात्रवृत्ति में गड़बड़ी करने वाले मामले मुझे बताएं

भोपाल। भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों की छात्रवृत्ति में गड़बड़ करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि यदि गड़बड़ी के कोई मामले आते हैं तो उनके संज्ञान में लाए जाए। वरिष्ठ भाजपा नेता आर्य और मंत्री मीना शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र ने अनुसूचित जाति के छात्रों को नए साल का तोहफा दिया है। पांच साल में करीब चार करोड़ अनुसूचित जाति के छात्रों को करीब 59 हजार करोड़ की छात्रवृत्ति मिलेगी।

हाई कोर्ट ने पंचायत सचिवों के तबादले पर लगाई रोक

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिये चार पंचायत सचिवों के तवादले पर रोक लगा दी। इसी के साथ राज्य शासन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिंदवाड़ा और जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति को नोटिस जारी कर जवाब-तलव कर लिया। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं को वर्तमान स्थान पर ही काम करते रहने की व्यवस्था दी है।

छिंदवाड़ा जिले में कार्यरत पंचायत सचिव सविता ठाकुर, शिवशंकर कोलारे, संजीव सूर्यवंशी और जगदीश सहारे की ओर से ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 18 दिसंवर, 2020 को उनका तवादला एक जनपद पंचायत से दूसरी जनपद पंचायत में कर दिया गया है। याचिका में कहा गया कि एक जनपद पंचायत से दूसरी जनपद पंचायत में तवादले के लिए दोनों जनपद पंचायतों की सामान्य प्रशासकीय समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। इसके वाद ही कलेक्टर द्वारा तवादला किया जा सकता है, जवकि तवादला आदेश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जारी कर दिया गया। सुनवाई के वाद एकल पीठ ने पंचायत सचिवों के तवादले पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल ने पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने दलील दी कि यह मामला मनमानी से संवंधित है। इस तरह नियमों के विपरीत निर्णय लेना अनुचित है। इसीलिए न्यायहित में हाई कोर्ट की शरण ली गई है। अंतरिम राहत यही अपेक्षित है कि याचिकाकर्ताओं को मौजूदा स्थान पर ही कार्यरत रहने की व्यवस्था दी जाए। हाई कोर्ट ने याचिका पर गौर करने के वाद अंतरिम आदेश पारित करते हुए अनावेदकों से जवाव-तलव कर लिया।

बीयू: छात्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए सिंगल विंडो कक्ष शुरू

भोपाल। बरकतउल्ला विवि में स्टूडेंट्स की समस्याओं के निराकरण के लिए सिंगल विंडो कक्ष स्थापित किए गए हैं। इसमें विवि के दो कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो छात्रों से उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन लेंगे और संबंधित शाखा से संपर्क कर उसका तत्काल निराकरण कराएंगे।

सिंगल विंडो के माध्यम से रिजल्ट संबंधी शिकायत, मार्कशीट, नामांकन, ट्रांसक्रिप्ट, पीएचडी आवेदन, डिग्री आदि की शिकायतों के निराकरण किए जाएंगे। ट्रांसक्रिप्ट, पीएचडी आवेदन आदि के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी शुरू की गई है। स्टूडेंट्स व कर्मचारियों की शिकायतों के निराकरण के लिए नए वर्ष के पहले दिन कुलपति प्रो. आरजे राव एवं कुलसचिव अजीत श्रीवास्तव द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें छात्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए सिंगल विंडो कक्ष सहित कई कदम उठाए गए।

जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश

सतना (नईदुनिया प्रतिनिधि)। राज्य सूचना आयोग ने पदोन्नति के मामले में डीईओ केएस कुशवाह एवं तत्कालीन सीईओ अमर बहादुर सिंह के विरुद्ध पदोन्नति प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों के संबंध में विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही तत्कालीन डीईओ पर 25 हजार जुर्माने का फैसला सुनाया है। इस संबंध में सहायक अध्यापक गोविंद्र प्रसाद गौतम ने बताया कि पदोन्नति के मामले को लेकर सीनियर अधिवक्ता रमाकांत त्रिपाठी के राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की गई थी जिसके बाद यह फैसला आया है।

बताया गया है कि अधिवक्ता रमाकांत त्रिपाठी द्वारा डीईओ सतना के समक्ष आरटीआई आवेदन 27 दिसम्बर 2019 को पेश किया था। जिसमें गोविंद प्रसाद गौतम सहायक अध्यापक शा. प्राथमिक शाला गुरजनहा को वर्ष 2015 में पदोन्नति में शामिल कराने के बाद उन्हें अपात्र माना जाकर उन्हें पदोन्नति नही दिए जाने के संबंध में जानकारी चाही गई थी। जिस पर समय सीमा में जानकारी उपलब्ध न कराए जाने के पश्चात प्रथम अपील दायर की गई। इसमें भी कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई। तब अधिवक्ता रमाकांत त्रिपाठी द्वारा द्वितीय अपील भोपाल में दायर की गई। जहां पर विस्तृत फैसला अपीलार्थी के पक्ष मे दिया गया। राज्य सूचना आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट लिखा है कि 10 शिक्षक जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया मे शामिल कराने का आदेश दिया गया था। परंतु तत्कालीन जिला पंचायत अधिकारी अमर बहादुर सिंह द्वारा व्यापक अनियमितता करते हुए पदोन्नति प्रक्रिया से वंचित रखा गया तथा उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई।

मंत्रालय कर्मचारी मिले प्रमुख सचिव वित्त से, ज्यादा वेतन और ब्याज कटौती से मांगी राहत

वेतन पर ब्याज कटौती बंद करने के लिए मोर्चा खोला

पीपुल्स ब्यूरो • भोपाल

मो.नं. 9425493055

मंत्रालय के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी से मिलकर पूर्व में उनके ज्यादा वेतन की मय ब्याज के कटौती को रोकने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि उनका ज्यादा वेतन निर्धारित होकर सालों तक मिलता रहा और अब ऑडिट में इस गड़बड़ी के सामने आने पर उनके वेतन के साथ ही 8% ब्याज भी वसूला जा रहा है, जिसके लिए कर्मचारी उत्तरदायी नही है।

इस बारे में मंत्रालय कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार पटेल ने बताया कि शनिवार को संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक, आलोक वर्मा, सलीम खान, आनंद भट्ट, यशवंत ढोणे, रचना बिलगैया, रामबाई, आशीष सोनी, मनोज बाजपेई, ठुकरदास प्रजापति, सतीश शर्मा, हरिशरण द्विवेदी, देव सिंह मरकाम आदि ने प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी से मिलकर कर्मचारियों को मिले वसूली नोटिस से अवगत कराया। प्रति कर्मचारी 5 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक की कटौती के नोटिस मिल चुके हैं। कई कर्मचारियों की तो कटौती भी शुरू हो गई है। इसमें भी 8 प्रतिशत ब्याज लगाया गया है। इस पर प्रमुख सचिव रस्तोगी ने आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा।

भोपाल। मंत्रालय कर्मचारियों ने प्रमुख सचिव वित्त को सौंपा ज्ञापन।

कर्मचारियों की इन मांगों पर भी हुई चर्चा

चार वर्ष से लंबित पदोन्नतियां, बीमा योजना, तृतीय समयमान में संशोधन, मंत्रालय हाऊसिंग प्रोजेक्ट समाप्त होने के बदले में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों में से आवास मंत्रालय अधिकारियों कर्मचारियों को आरक्षित किया जाना।

वेतन कटौती वाले कर्मचारी

सहायक ग्रेड-3 स्तर के मंगल सिंह, हरगोविंद लोधी, गोविंद बाथम, एकनारायण शर्मा, अंजुला गुप्ता, बसंत दीक्षित, श्याम सिंह, रामभरोसे शर्मा, धीरेंद्र सिंह, महेंद्र अवधिया, अमरजीत पटेल, राजेंद्र तिवारी, यज्ञसेन वर्मा, सुदामा वर्मा, ताराबाई उपाध्याय, उमेश कुमार श्रीवास, संतोष सोनी, मोहिनी शर्मा, सावित्री, कृपाल रावत, ठाकुर दास, दयाराम पाल, बाबूराम न्यौपाने, संतोष श्रीवास्तव, सुनीता सौंधिया, रमेश मिश्रा, लखनलाल लोधी, शेख इकबाल, रामसिया पाल, बालकिशन बाथम, भगवत प्रसाद रायकवार, मानसिंह बघेल, प्रकाशचंद्र बिरमा, सेवानिवृत्त हो चुके गीता मिश्रा, कामता प्रसाद वर्मा।

किताब देखकर भी पास नहीं होने से बढ़ी शिक्षा विभाग की परेशानी

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में बंद चल रहे स्कूलों की वजह से शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के लिए इस बार पुस्तक परीक्षा पद्धति पर अर्द्धवार्षिक परीक्षा ली गई है। इस परीक्षा के जो परिणाम सामने आए है उससे, विभाग की परेशानी बढ़ गई है। इसकी वजह है अनुमान से अधिक छात्रों का अनुत्तीर्ण हो जाना। झाबुआ में जहां सर्वाधिक 50 प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो वहीं भोपाल में भी तीस प्रतिशत छात्र परीक्षा पास नहीं कर सके हैं। अगर प्रदेश भर में हुई परीक्षा का औसत देखा जाए, तो इस परीक्षा में औसत रुप से 29 प्रतिशत विद्यार्थी पास होने में असफल रहे हैं।

दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस तरह की परीक्षा का पहली बार प्रयोग किया गया था, जिसके तहत नवमीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों का संशोधन परीक्षण के नाम पर छमाही परीक्षा ली गई। यह परीक्षा अधिकांश विद्यार्थियों ने घर से दी। हालांकि भोपाल में यह परीक्षा स्कूल में कराई गई। इस परीक्षा में प्रदेश के 78 प्रतिशत विद्यार्थी पास हो सके। इसमें नवमीं कक्षा में 70 प्रतिशत, दसवीं में 78 प्रतिशत, ग्यारहवीं में 88 प्रतिशत और बारहवीं में 83 प्रतिशत पास हुए हैं। खास बात यह है कि इस परीक्षा में पांच जिले ऐसे रहे हैं, जहां पर परिणाम 94 प्रतिशत रहा है। इन जिलों में इंदौर, बालाघाट, सागर, सीहोर, नीमच शामिल है। इसी तरह से सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों मुरैना, शिवपुरी, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिले शामिल हैं।

अब मुख्य परीक्षा पर पूरा फोकस

पुस्तक परीक्षा पद्धति पर परीक्षा परिणाम को लेकर विभाग समीक्षा बैठक में चिंता जाहिर कर चुका है। बैठक में कहा गया कि जब किताब से परीक्षा देने पर परिणाम 80 प्रतिशत से कम रहा है, तो फिर वार्षिक परीक्षा के परिणाम का तो बुरा हाल होगा। यही वजह है कि अब आला अधिकारियों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को मुख्य परीक्षा के लिए लक्ष्य तय करने को कहा है।

तीन लाख से अधिक ने नहीं दी परीक्षा

कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार तिमाही परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। इस वजह से पहली बार छमाही परीक्षा पुस्तक परीक्षा पद्धति के आधार पर कराई गई। इस परीक्षा में 23 लाख 26 हजार 999 में से 18 लाख 6 हजार 933 विद्यार्थी पास हुए जबकि, 2 लाख 4 हजार 784 अनुत्तीर्ण हुए हैं। खास बात यह है कि इस परीक्षा में 3 लाख 15 हजार 282 विद्यार्थी शामिल ही नहीं हुए।

यह भी माने जाएंगे असफल

इस परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले को ए प्लस, 75 प्रतिशत से अधिक पर ए, 60 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले को बी, 45 प्रतिशत से अधिक लाने पर सी, 33 प्रतिशत से अधिक लाने वाले को डी-श्रेणी दी गई है। वहीं 20 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले को ई-1 और ई-2 श्रेणी दी गई है, यानि ई-1 व ई-2 श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी अनुत्तीर्ण माने जाएंगे।

दुकानें हटाने मैदान पर उतरे शिक्षक, रणनीति बनाकर कार्रवाई की दरकार

चाय-पान के दुकानदारों से कन्या धवारी के शिक्षकों ने कहा-

सर, प्लीज स्कूल गेट के सामने का अतिक्रमण हटा लीजिए

'सर, यह विद्यालय है जहां छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं, लेकिन आप लोगों द्वारा स्कूल से सटाकर दुकानें और ठेले लगा लेने से छात्राओं को दिक्कतें होती हैं, कृपया आप लोग कुछ दूर दुकानें लगाएं'। छात्राओं को पढ़ाने वाले कन्या धवारी विद्यालय के अध्यापक शनिवार को कुछ ऐसी ही गांधी गिरी दिखाते हुए दुकानदारों से अतिक्रमण हटाने के लिएमनुहार करते नजर आए ।

स्टार समाचार | सतना

दरअसल वे स्कूल से सटकर चौतरफा लगी दुकानों को हटवाने का प्रयास कर रहे थे। यूं तो यह उनका काम नहीं है लेकिन जिनके पास अतिक्रमण हटाने का जिम्मा है उनको इतना समय नहीं है कि वे स्कूलों के आसपास भी जाकर देखें, नतीजतन शिक्षकों को ही मैदान पर उतरना पड़ा। बताया गया कि कन्या धवारी हायर सेकेंडरी स्कूल के दक्षिण दिशा की तरफ बने गेट के सामनें पिछले डेढ़ माह से ठेले लगा कर अतिक्रमण कर रखा है और रास्ता ब्लॉक है। यहां चाय-पान व गुटखे के ठेले धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे हैं। विद्यालय प्राचार्य सुभाषचंद्र मिश्र अपने स्टाफ के साथ ठेले वालों से बात की और वहां से हटने अन्यत्र दूसरी जगह लगाने के लिए कहा। हालांकि सौम्यता से किया गयाशिक्षकों के अनुरोध का कोई असर दुकानदारों पर नहीं पड़ा और शिक्षकों के स्कूल में घुसते ही सभी दुकानदार उसी तरह जम गए जैसे वे जमे हुए थे। कन्या धवारी विद्यालय के शिक्षकों के इस प्रयास ने शहर की स्कूलों से सटे अतिक्रमण की पोल खोल दी है। विद्यालय प्राचार्य ने रास्ते से अतिक्रमण हटवाने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखा है जिसमें जल्द-जल्द अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है।

कई सरकारी स्कूल अतिक्रमित

शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक की सरकारी स्कूलें अतिक्रमण का शिकार है। शहर मे ही देखें तो कन्या धवारी के अलावा एमएलबी स्कूल भी ऐसे ही अतिक्रमण का शिकार है जिसकी दीवारे दिन मे दुकानदारों की दीवार में तब्दील हो जाती हैं। एमएलबी स्कूल की दीवार से सटी दुकानें जहां वहां पढ़ने वाली छात्राओं को परेशानी मे डालती है वहीं स्टेशन रोड की यातायात व्यवस्था को भी चौपट करती हैं। कन्या धवारी व एमएलबी दोनो ही छात्राओं के विद्यालय हैं ऐसे में इन स्कूलों से सटी दुकानें शोहदों का भी अड्डा बन जाती हैं जो छात्राओं से छीटाकशी कर कई बार विवाद खड़े करते हैं। व्यंकट1, व्यंकट 2 भी अतिक्रमण का शिकार हैं पर इनका एरिया इतना बड़ा है कि इनका अतिक्रमण छात्रों को प्रभावित नही करता है।

पान गुटखा दुकानों के नियम का पालन नहीं

नियम है कि स्कूल बाउंड्री से 100 मीटर की दूरी तक पान-मसाला या गुटखे की दुकाने प्रतिबंधित हैं लेकिन कई जगह तो स्कूल बाउंड्री से सटा कर ही पान गुटखे के ठेले चल रहे हैं। कई स्कूलों से सटकर ऐसे दुकानें खोली गई हैं कि कोई भी छात्र स्कूल के भीतर से केवल हाथ निकालकर गुटखा खरीद सकता है।

पत्र लिखकर जानकारी मगाई जाएगी। यदि किसी प्राचार्य ने अतिक्रमण की शिकायत की तो प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर अतिक्रमण हटाया जाएगा।

केएस कुशवाह, जिला शिक्षा अधिकारी

गेट के बाहर ठेले लगते हैं जिससे रास्ता ब्लाक हो जाता है। हमने सोचा कि शायद समझाइश से दुकानदार दिक्कतें समझ लें हमने ननि आयुक्त को भी पत्र लिखा है।

सुभाष चंद्र मिश्र, प्राचार्य, शासकीय कन्या सेकेंडरी स्कूल धवारी

फिलहाल हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है लेकिन यदि कोई प्राचार्य ऐसी शिकायत बताते है तो त्वरित कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जाएगा। सख्ती से अभियान शुरू किया जाएगा।

रमाकांत शुक्ला, ननि अतिक्रमणरोधी दस्ता प्रभारी

महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया 5 जनवरी तक

सतना (नव स्वदेश)। स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों में छठवें चरण की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 5 जनवरी 2021 तक चालू है। महाविद्यालय, पाठ्यक्रम एवं विषय समूह का निर्धारित प्रारूप में पृथक-पृथक महाविद्यालय में विकल्प 4 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक दिया जा सकेगा। महाविद्यालय द्वारा सीएलसी चरण की मेरिट सूची 4 जनवरी को अपराहन 3 बजे जारी की जाएगी। आवंटित महाविद्यालयों में पोर्टल के माध्यम से डिजिटल ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 4 एवं 5 जनवरी को किया जा सकेगा। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय एवं संस्थान द्वारा प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग 5 जनवरी 2021 तक की जाएगी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों में प्रवेश समय-सारिणी

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों बीएड, एमएड, बीपीएड एवं बीएडएमएड एकीकृत 3 वर्षीय तथा बीएबीएड, बीएससी, बीएड, बीएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का चतुर्थ अतिरिक्त चरण 12 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया है। अपर आयुक्त उच्च शिक्षा ने बताया कि नवीन पंजीयन 3 जनवरी 2021 तक होंगे। ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश के लिए पंजीयन नहीं करा सके हैं वह पंजीयन कर अतिरिक्त चरण में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे। चतुर्थ अतिरिक्त चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुनः शिक्षण संस्थाओं का चयन एवं वरीयता प्राप्त करने की तिथि 4 जनवरी 2021 तक होगी। आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन, नवीन पंजीकृत आवेदकों का बीपीएड एवं एमपीएड के लिए फिटनेस तथा प्रोफिशिएंसी टेस्ट निर्धारित हेल्प सेंटर पर तथा अंको को पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि 4 जनवरी 2021 तक होंगी।

समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन 5 जनवरी को शाम 6 बजे किया जाएगा। मेरिट एवं वरीयता अनुसार अतिरिक्त चरण में सीट आवंटन 9 जनवरी को होगी। आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के लिए शुल्क भुगतान की रसीद एवं टीसी तथा माइग्रेशन प्रस्तुत करने की तिथि 9 जनवरी से 12 जनवरी तक निर्धारित की गई है।

40 विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने का मौका

भोपाल। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च अध्ययन करने के लिए विभाग द्वारा आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। इस वर्ष अब तक करीब 10 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि 40 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के रूप में मंजूर की गई है। वहीं प्रदेश के 51 जिलों में 100 सीटर पिछड़ा वर्ग बालक एवं 50 सीटर कन्या छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। इन छात्रावासों का संचालन पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। उज्जैन जिले में 100 सीटर बालक तथा 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन का निर्माण पूर्णता की ओर है।

आदिम-जाति कल्याण विभाग की शालाओं के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

सतना (नव स्वदेश)। आदिम-जाति कल्याण विभाग की शालाओं को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्र प्रारंभ करने एवं शालाओं के संचालन के संबंध में विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। दिशा-निर्देश गृह मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन 30 सितम्बर 2020 के आधार पर कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जारी किये गये हैं। बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिये विद्यालय नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिये संचालित होंगे। विद्यालयों में विद्यार्थियों को इस प्रकार से आमंत्रित किया जायेगा, कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एक साथ अधिक न हो। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। यह माता-पिता अथवा अभिभावकों की सहमति पर निर्भर करेगा।

विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को वितरित किया सूखा राशन

विद्यालयीन छात्र-छात्राओं को सूखा राशन बांटते जनप्रतिनिधि।

दतिया, ब्यूरो

मध्यान्ह भोजन की जगह विद्यालयों में बच्चों को सूखा राशन वितरित करने की यह योजना म.प्र. शासन के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की मंशानुसार और उनके अथक प्रयासों से दतिया जिले में सर्व प्रथम प्रारंभ की गई है। प्रदेश सरकार छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यालयों के बच्चों को मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत सूखी खाद्यान्न सामग्री दाल एवं तेल वितरित करा रही है। यह बात ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में खाद्यान्न सामग्री बांटते हुए जनप्रतिनिधियों ने कही।

जिला पंचायत सदस्य श्रीमती लक्ष्मी रामजी यादव एवं सरपंच लखन यादव ने ग्राम गरैरा व धुवियापुरा के विद्यालयों में बच्चों को सूखा राशन वितरित किया। इस दौरान सीएसी नत्थूसिंह यादव, प्रधानाध्यापक अशोक कुमार गुप्ता, बृजपाल यादव, शिक्षक श्रीमती कल्पना तिवारी, अखिलेश गुप्ता, अंगूरी यादव, संतोषी यादव उपस्थित रहे। इसी प्रकार बगेदरी में नारायणी गुप्ता, स्वप्नल त्रिपाठी व ग्रामीणजन उपस्थित रहे। जनपद सदस्य क्रांति राय ने ग्राम कमरारी, वनवास, जौहरिया, नुनवाहा, खरग आदि विद्यालयों में दो-दो किलो के दाल के पैकेट व आधा-आधा किलो के तेल के पैकेट बच्चों को वितरित किए। इस दौरान सीएसी महेन्द्र मुडिआ, प्रधानाध्याक्षक उमाचरण मिर्धा, सतीष गुप्ता, कमर जहां खान, मदन मोहन शर्मा, महेन्द्र यादव, मुकेश प्रजापति सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

पांच प्रतिशत डीए और सातवें वेतनमान का एरियर देने की मांग

मगरौनी, नि.प्र.। मध्य प्रदेश के संवेदनशील तथा लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कर्मचारी नेता एसएस कुशवाह, हरगोविन्द दुबे, नाथूराम मिश्रा, विष्णु मिश्रा, नाथूराम दुबे, हांजी समद खां, आरके माथुर, जेपी रावत डीके माहेश्वरी, भागचंद आर्य, राजेश आर्य, सैतान रावत, जेपी रावत आदि ने राज्य सरकार से करबद्ध प्रार्थना की है कि सातवें वेतनमान ऐरियर्स, पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा इंक्रिमेंट की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए ताकि इस भीषण महंगाई में कर्मचारियों को राहत मिल सके।

माध्यमिक विद्यालय सांरगगढ में सूखा राशन का वितरण, उपस्थित रहे विद्यार्थी

हरिभूमि न्यूज अमरपुर/डिण्डौरी । शासन की मंशानुसार कोरोना संक्रमण में मध्यान्ह भोजन खाद्य सुरक्षा भत्ता अंतर्गत मध्यान्ह भोजन परिषद भोपाल एंव जिला पंचायत डिण्डौरी के निर्देश पर नवीन माध्यमिक शाला सारंगढ़ एवं प्राथमिक शाला सारंगढ़ में मध्यान्ह भोजन अंतर्गत सूखा राशन दाल-तेल का वितरण किया गया वितरण अवसर पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी बी.के.चीचाम, बी.आर.सी.सी. सुरेन्द्र पटेल, संकुल प्राचार्य अमर सिंह ठाकुर, बी.ए.सी. शेख अमजद, सरपंच जानू सिंह कुशराम, हरे सिंह पट्टा, मकसूद खान, रईस अहमद जैदी जन शिक्षक, रामकुमार यादव जन शिक्षक, अरुण कुमार बट्टे, नीलम कुमार धनंजय, सुखचैन सिंह धुर्वे की उपस्थिति में किया गया इस अवसर पर प्रधानाध्यापक मधुदीप उपाध्याय ने बताया कि ब्वअपक-19 काल में स्कूल बंद है, वर्तमान में शैक्षिक व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु मोहल्ला क्लास का संचालन किया जा रहा है। वहीं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम बंद है, बच्चों के पोषण हेतु सूखा राशन चांवल दाल तेल का वितरण किया जा रहा है, उसी क्रम में 02 जनवरी को माध्यमिक शाला के बच्चों 73 दिवस का 783 मिली. तेल एवं 3 किलोग्राम राहर की दाल, तथा प्राथमिक शाला में 525 मिली. तेल तथा 2 किलोग्राम दाल का वितरण किया गया है। बीआरसी सुरेन्द्र पटेल ने बताया कि इसी तरह से वितरण पूरे विकासखंड अमरपुर अंतर्गत चांवल एवं दाल तेल का वितरण किया जा रहा है, विकास खंड शिक्षा अधिकारी बी. के. चीचाम ने पालकों से अपने बच्चों को नियमित रूप से मोहल्ला क्लास भेजने तथा शैक्षिक गुणवत्ता में ध्यान देने हेतु कहा। आज के इस वितरण कार्यक्रम में शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष लीलाराम बघेल संतोषी बाई टांडिया, गोमती पट्टा मनोनीत पंच सदस्य, सभी बच्चे एवं पालक उपस्थित रहे। आज के सुखा राशन वितरण कार्यक्रम में प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला में शत प्रतिशत वितरण किया गया जिसमें मुख्य रूप से अभिनेश कुमार यादव, राम प्रसाद यादव, संतोष कुमार मसराम एवं शाला प्रबंधन समिति के सदस्य पालक अभिभावक छात्र छात्राओं के साथ उपस्थित रहे ।

यूजी-पीजी में एडमिशन के लिए 4 हजार 43 ने कराया दस्तावेज का सत्यापन, कल जारी होगी मेरिट सूची

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यूजी-पीजी की 4 लाख 73 हजार 452 सीटों के लिए अतिरिक्त छठवां राउंड चलाया जा रहा है। शनिवार को दस्तावेज सत्यापन का अंतिम दिन था, इसमें कुल रजिस्टर्ड 4717 स्टूडेंट्स में से 4043 ने अपने दस्तावेजों के सत्यापन करा लिए हैं। सत्यापित स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग के साथ ही 4 जनवरी को मेरिट लिस्ट जारी होगी और उसी समय से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। यह अतिरिक्त राउंड 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेगा। पांच राउंड में हुए एडमिशन के बाद भी कई कॉलेजों में छात्रों द्वारा एडमिशन नहीं होने की शिकायत की गई थी।

बीई में 30 हजार तक नहीं पहुंचा एडमिशन का आंकड़ा

तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीई) द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों की लगभग 27 हजार सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त राउंड चलाया, लेकिन कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। बीई में अतिरिक्त राउंड में केवल 744 व पॉलिटेक्निक में 690 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। इस तरह पिछले पांच राउंड में 29,020 छात्रों को मिलाकर छठवें राउंड तक एडमिशन का आंकड़ा 29,764 तक ही पहुंच पाया है। अभी भी 26,348 सीटें खाली हैं।

जनवरी में अर्द्धवार्षिक एवं फरवरी-मार्च में वार्षिक मूल्यांकन

कक्षा 1 से 8वीं के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम के लिए बनाई गई नई व्यवस्था

भास्कर न्यूज. सतना

शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से आठवीं तक के विद्यार्थियों का मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर होगा। बताया गया कि कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को वर्कशीट दी जाएगी। इसके आधार पर उनका अद्र्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थियों का अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन जनवरी माह में एवं वार्षिक मूल्यांकन फरवरी एवं मार्च में किया जाएगा।

कौशल आधारित होंगे प्रश्न • राज्य शिक्षा केंद्र ने माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी शासकीय शालाओं में शिक्षण सत्र 2020-21 में कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों के अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन (प्रतिभा पर्व) एवं वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कक्षा पहली एवं दूसरी के बच्चों को शालाओं से ही अभ्यास पुस्तिका दी जाएगी, जिसके अंत में वर्कशीट होगी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय के प्रश्न होंगे।

कक्षा तीसरी से आठवीं तक के बच्चों को दी जाने वाली वर्कशीट में कौशल आधारित प्रश्न और प्रोजेक्ट वर्क होगा। वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर और प्रोजेक्ट वर्क लिखने के लिए स्थान रहेगा।

रोजमर्रा की सामग्री से बनाएंगे प्रोजेक्ट

वर्कशीट में 60 प्रतिशत लिखित एवं 40 प्रतिशत अंक प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट वर्क में छात्रों से कोई मॉडल नहीं बनवाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट वर्क घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों से पूछ कर पूरे किए जा सकेंगे। विद्यार्थियों का अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन 20 से 30 जनवरी के मध्य एवं वार्षिक मूल्यांकन 15 से 28 फरवरी और 10 से 20 मार्च के बीच किया जाएगा। परीक्षाफल का निर्धारण अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। हमारा घर-हमारा विद्यालय अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों के सह-शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन कर ग्रेड का निर्धारण करेंगे।

किताब देखकर भी पास नहीं होने से बढ़ी शिक्षा विभाग की परेशानी

भोपाल निप्र

कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में बंद चल रहे स्कूलों की वजह से शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के लिए इस बार पुस्तक परीक्षा पद्धति पर अर्द्धवार्षिक परीक्षा ली गई है। इस परीक्षा के जो परिणाम सामने आए हैं उससे, विभाग की परेशानी बढ़ गई है। इसकी वजह है अनुमान से अधिक छात्रों का अनुत्तीर्ण हो जाना। झाबुआ में जहां सर्वाधिक 50 प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो वहीं भोपाल में भी तीस प्रतिशत छात्र परीक्षा पास नहीं कर सके हैं। अगर प्रदेश भर में हुई परीक्षा का औसत देखा जाए, तो इस परीक्षा में औसत रुप से 29 प्रतिशत विद्यार्थी पास होने में असफल रहे हैं।

दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस तरह की परीक्षा का पहली बार प्रयोग किया गया था, जिसके तहत नवमीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों का संशोधन परीक्षण के नाम पर छमाही परीक्षा ली गई। यह परीक्षा अधिकांश विद्यार्थियों ने घर से दी। हालांकि भोपाल में यह परीक्षा स्कूल में कराई गई। इस परीक्षा में प्रदेश के 78 प्रतिशत विद्यार्थी पास हो सके। इसमें नवमीं कक्षा में 70 प्रतिशत, दसवीं में 78 प्रतिशत, ग्यारहवीं में 88 प्रतिशत और बारहवीं में 83 प्रतिशत पास हुए हैं। खास बात यह है कि इस परीक्षा में पांच जिले ऐसे रहे हैं, जहां पर परिणाम 94 प्रतिशत रहा है। इन जिलों में इंदौर, बालाघाट, सागर, सीहोर, नीमच शामिल है। इसी तरह से सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों मुरैना, शिवपुरी, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिले शामिल हैं।

अब मुख्य परीक्षा पर पूरा ध्यान

पुस्तक परीक्षा पद्धति पर परीक्षा परिणाम को लेकर विभाग समीक्षा बैठक में चिंता जाहिर कर चुका है। बैठक में कहा गया कि जब किताब से परीक्षा देने पर परिणाम 80 प्रतिशत से कम रहा है, तो फिर वार्षिक परीक्षा के परिणाम का तो बुरा हाल होगा। यही वजह है कि अब आला अधिकारियों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को मुख्य परीक्षा के लिए लक्ष्य तय करने को कहा है।

स्कूल यूनीफॉर्म की सीधी खरीदी का मामला हाईकोर्ट में

मप्र भंडारण क्रय अधिनियम का उल्लंघन

पीपुल्स ब्यूरो ● जबलपुर

editor@peoplessamachar.co.in

बच्चों की यूनीफॉर्म को लेकर मप्र भंडारण क्रय अधिनियम-2015 के खिलाफ एक सर्कुलर जारी कर ओपन मार्केट से भी खरीदी किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस संजय द्विवेदी की अवकाशकालीन पीठ ने मामले में शासकीय अधिवक्ता को जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को निर्धारित की है। यह मामला भोपाल की स्व-सहायता समूह एडवांस वूमेन लाईव-ली-हुड आर्गेनाईजेशन की चेयरमैन सपना नेरकर की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि मप्र भंडारण क्रय अधिनियम-2015 के तहत शासकीय विभागों में जो भी खरीदी होगी। सरकार ने प्रदेश के 66 लाख बच्चों की यूनीफॉर्म महिला स्व-सहायता समूहों से बनवाने का निर्णय लेते हुए धारा-6 के तहत पॉवर लूम व कुटीर उद्योग से ही कपड़ा खरीदने की व्यवस्था दी थी, ताकि समूह यूनीफार्म का निर्माण कर सरकार को देगी।

ये कहा याचिकाकर्ता ने

नवंबर 2020 में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें ओपन मार्केट से भी कपड़ा खरीदने की अनुमति प्रदान की गई। यदि ऐसा हुआ तो कपड़े पर अनियमितताएं होने पर उसका खामियाजा सरकार को होगा, इतना ही नहीं स्व सहायता समूहों को भी नुकसान होगा।

दो साल पहले भी 45 हजार स्कूलों को किया गया था मर्ज

दाखिले कम होने से मजरे-टोले के एक लाख स्कूलों को किया जाएगा मर्ज

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों की बड़ी सर्जरी करने की तैयारी है। कम एडमीशन वाले मजरे-टोले के आसपास चल रहे एक लाख स्कूलों को पास के ही स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। संकुल प्राचार्यों से इस संबंध में जानकारी मांगी गई है।

दो साल पहले भी प्रदेश के 45384 स्कूलों को 20656 परिसर में मर्ज किया गया था इनमें 40 से कम नामांकन वाली 40102 प्राथमिक शाला और 6221 मिडिल स्कूलों को मर्ज किया गया था। उस समय अकेले भोपाल में 413 स्कूल मर्ज किए गए थे। हालांकि पालकों की माने तो कई स्कूल अब बहुत अधिक दूरी पर हैं। पहले स्कूल पास होने पर चंद मिनिटों में बच्चे घर से स्कूल और स्कूल से घर आ जाते हैं। स्कूल दूर होने पर बच्चों की चिंता भी सताती है। बता दें कि सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाने की रूपरेखा 2 साल पहले पूर्व शिक्षा मंत्री विजय शाह के समय शुरू की गई थी। उस समय एक शाला एक परिसर के तहत प्रदेश के हाई सेकंडरी के 1941 स्कूल, 2972 हाई स्कूल, 20235 मिडिल स्कूल एवं 20233 प्राथमिक शाला में शामिल की गई थी।

संकुल प्राचार्यों से मंगाई प्रदेश के स्कूलों की जानकारी, पालक बोले-अब स्कूल हो गया दूर

सीएम राइस स्कूल के लिए हो रही सारी कवायद

यह पूरी कवायद सीएम राइज स्कूल के लिए की जा रही है। प्रदेश सरकार यहां के छात्र छात्राओं को विश्वस्तरीय सुविधा देने के लिए प्रदेश के 9200 स्कूलों को हाईटेक बनाने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है कि अभिभावकों को निजी स्कूलों की मनमानी से राहत मिले और वे सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं। इसके लिए संकुल केंद्र प्राचार्य से 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों की जानकारी मांगी है। प्रदेश में 3000 संकुल केंद्र संचालित हैं। हर संकुल प्राचार्य को क्षेत्र के 5000 स्कूलों की सूची भेजना है। इनमें से सीएम राइस के लिए 33 स्कूलों का चयन किया जाएगा। इन स्कूलों के डेवलपमेंट पर प्रति स्कूल 20 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। सरकार ने 3 साल में सभी स्कूल शुरू करने का लक्ष्य रखा है।

स्कूलों की तरह विलय होंगे प्रदेश के 51 कॉलेज

स्कूलों की तरह ही कम एडमीशन वाले प्रदेश के 51 कॉलेजों को सरकार बंद करने की जगह दूसरे कॉलेजों में मर्ज करेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी है। इस सूची में ऐसे कॉलेज हैं जहां छात्रों की संख्या 100 से कम है। इस साल जिन छात्रों ने भी इन कॉलेजों में प्रवेश लिया है उन्हें दूसरे कॉलेजों में ट्रांसफर किया जाएगा। जानकारी के अनुसार ऐसे कॉलेज में इस साल करीब 3 हजार स्टूडेंट एडमीशन ले चुके हैं। इन कॉलेजों में पारंपरिक कोर्सेस जैसे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस विषय की पढ़ाई होती है। ये कॉलेज अतिथि विद्वानों के ही भरोसे चल रहे थे। इसी वजह से युक्तियुक्तकरण योजना के तहत कॉलेजों के विद्यार्थियों और स्टाफ को शिफ्ट किया जाएगा। सबसे ज्यादा सतना जिले के कॉलेज हैं। यहां मर्ज कॉलेजों की संख्या चार है। इसी तरह उज्जैन, सिंगरौली, शिवपुरी, सीधी, डिंडोरी में तीन-तीन, अनूपपुर, सीहोर, हरदा, शहडोल, मंडला, रायसेन, धार, श्योपुर, बड़वानी और बुरहानपुर में दो-दो, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, आगर मालवा, ग्वालियर, होशंगाबाद, कटनी, मंदसौर, मुरैना, नीमच, कटनी, सागर, पन्ना, रीवा और रतलाम के एक-एक कॉलेज को मर्ज किया जाएगा।